गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 214
दि. 05.12.2025,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

दिल्ली की रात में उतरी कूटनीति की चमक: पुतिन की ऐतिहासिक भारत यात्रा से रिश्तों में नई गर्माहट

(जीएनएस)। नई दिल्ली की हवा में गुरुवार रात एक खास उत्साह महसूस किया गया, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जटिलता और वैश्विक तनावों के बीच यह यात्रा सिर्फ औपचारिक कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि दो पुराने मित्र देशों के विश्वास, परंपरा, साझेदारी और भविष्य की दिशा को तय करने का एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षण बनकर उभरी, जिसकी गूंज आने वाले वर्षों तक सुनी जाएगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मौजूद थे और जब दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को गले लगाकर स्वागत किया, तो उस दृश्य ने यह संदेश साफ कर दिया कि भारत–रूस मित्रता की ऊष्मा आज भी उतनी ही मजबूत है, जितनी शीतयुद्ध के दौर में थी। पुतिन ने एयरपोर्ट पर भारतीय संस्कृति की झलक पेश करते कार्यक्रम को ध्यान से देखा, सराहा और मुस्कुराते हुए उसका आनंद लिया। राजधानी का माहौल स्वागत बैनरों, सुरक्षा तैयारियों और उत्सुक निगाहों के बीच मानो एक बड़े ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन गया।

भारत और रूस के बीच यह वार्षिक शिखर सम्मेलन ऐसे समय में आयोजित हो रहा है, जब दुनिया शक्ति-संतुलन के नए अध्याय लिख रही है। अमेरिका द्वारा भारत पर बढ़ाए टैरिफ, यूरोप की राजनीतिक अस्थिरता और यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक कूटनीति को कई खेमों में बाँट दिया है। लेकिन इन सबके बीच भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम है और रूस के साथ अपने संबंधों को उसी धैर्य, संतुलन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा रहा है, जिसने पिछले आठ

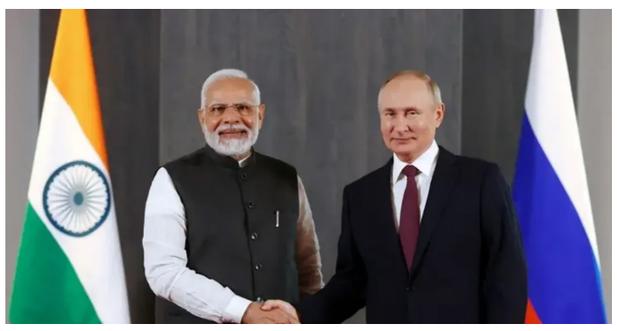

दशकों में दोनों देशों की साझेदारी को मजबूत बनाए रखा है। मोदी और पुतिन की बैठक इस बात का प्रतीक है कि भारत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अपनी जगह और भूमिका खुद तय करता है, और मॉस्को नई दिल्ली को लंबे समय से एक भरोसेमंद, स्थिर और रणनीतिक साथी के रूप में देखता है।

इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण घोषणाओं और समझौतों की उम्मीद की जा रही है। रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने से लेकर ऊर्जा सुरक्षा के नए अध्याय लिखने तक, व्यापारिक संबंधों को बाहरी दबावों से सुरक्षित रखने से लेकर कामगारों के आवागमन को सरल बनाने तक—दोनों देश भविष्य की साझेदारी को एक नई दिशा देने की तैयारी में हैं। छोटे मॉड्यूलर परमाणु संयंत्रों पर संभावित सहयोग आने वाले वर्षों में भारत की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित और संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा, यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ भारत के प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा की संभावना है, जो व्यापार को नई गति और नई भौगोलिक दिशा दे सकता है। रूस द्वारा भारत में 'इंडिया चैनल' की शुरुआत सांस्कृतिक संवाद और जन-से-जन संबंधों को और भी जीवंत करेगी।

शुक्रवार का दिन दोनों देशों के लिए व्यस्त और ऐतिहासिक होने वाला है। पुतिन राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और यह संदेश देंगे कि भारत की आत्मा और उसके महापुरुषों का सम्मान, मॉस्को की कूटनीति का भी हिस्सा है। राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत के बाद हैदराबाद हाउस में मोदी–पुतिन वार्ता का मुख्य चरण शुरू होगा। यहाँ होने वाली बातचीत में कई ऐसे फैसले लिए जाने की उम्मीद है, जो आने वाले दशकों में भारत–रूस संबंधों की दिशा और गहराई को निर्धारित करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री मोदी पुतिन और उनके प्रतिनिधिमंडल के लिए भोज का आयोजन करेंगे, जहाँ सिर्फ पकवान ही नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीतिक योजनाएँ भी साझा की जाएँगी। देर शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के राज्य भोज में शामिल होने के बाद पुतिन रात करीब नौ बजे भारत से प्रस्थान करेंगे।

यह यात्रा इसलिए भी विशेष है क्योंकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से यह पुतिन की भारत की पहली यात्रा है। ऐसे समय में जब दुनिया में रूस को लेकर कई तरह की राजनीतिक धारणाएँ बनाई जा रही हैं, भारत और रूस का यह खुला संवाद यह बताता है कि दोनों देशों का संबंध बाहरी प्रभावों से नहीं, बल्कि परस्पर सम्मान, ऐतिहासिक मित्रता और साझा हितों पर आधारित है। वर्ष 2000 में दोनों देशों के बीच हुई सामरिक साझेदारी की घोषणा ने जिस नींव को स्थापित किया था, आज वह और गहरी, मजबूत और बहुआयामी होती जा रही है। रक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान, ऊर्जा, संस्कृति और शिक्षा—किसी भी क्षेत्र को देखें, भारत और रूस साथ-साथ खड़े दिखाई देते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के स्वागत के दौरान कहा—"मुझे अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन का दिल्ली में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। मैं आज शाम और कल हमारी बैठकों को लेकर आशान्वित हूं। भारत और रूस की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है और इससे हमारे लोगों को अपार लाभ हुआ है।" यह बयान सिर्फ वर्तमान परिस्थिति को नहीं, बल्कि दशकों पुराने उस बंधन को भी दोहराता है जिसमें विश्वास, समझ और सहयोग हमेशा सबसे आगे रहा है।

भारत और रूस के बीच का रिश्ता सिर्फ कूटनीति का पन्ना नहीं, बल्कि पुरानी मित्रता का पुल है—जो भू-राजनीतिक तूफानों में भी नहीं टूटा, जो आर्थिक संकटों में भी नहीं हिला, और जिसने नई पीढ़ियों के लिए सहयोग की अनगिनत संभावनाएँ खोली हैं। पुतिन की यह भारत यात्रा उसी पुल पर एक और मजबूत पत्थर जोड़ती है, और बताती है कि बदलते समय में भी कुछ संबंध सिर्फ जीवित ही नहीं रहते, बल्कि और भी अधिक सार्थक और शक्तिशाली हो जाते हैं।

शांति से पहले सहयोग नहीं: लेबनान के प्रधानमंत्री का दो टूक संदेश, इज़राइल के साथ सामान्य संबंधों की राह अब भी दूर

(जीएनएस)। बेयरूत की राजनीतिक फिज़ा में गुरुवार को एक नया हलचलभरा बयान गूंजा, जिसने मध्य-पूर्व की भू-राजनीतिक बहस को फिर केंद्र में ला दिया। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने स्पष्ट और ठोस शब्दों में कहा कि इज़राइल के साथ किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग या वार्ता तभी संभव है जब दोनों देशों के बीच स्थायी शांति स्थापित हो। वर्तमान परिस्थितियाँ, सीमा की बेचैनी, सैन्य कार्रवाइयों और दोनों पक्षों के बीच गहरे अविश्वास को देखते हुए, यह मार्ग इतना सरल और सहज नहीं दिखता। प्रधानमंत्री सलाम का शब्दों में संयम होते हुए भी, उनके बयान का स्वर बेहद दृढ़ था—लेबनान किसी भी तरह के आर्थिक रिश्ते पर विचार करने से पहले अपनी सुरक्षा और सार्वभौमिक अधिकारों की गारंटी चाहता है।

इज़राइल की ओर से हाल ही में आर्थिक सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई गई थी। इसके जवाब में सलाम ने कहा कि किसी भी आर्थिक बातचीत की नींव सामान्य संबंधों पर टिकी होती है, और सामान्यीकरण शांति स्थापित होने के बाद ही संभव है। उनकी यह

टिप्पणी उस ऐतिहासिक हकीकत की याद दिलाती है जिसमें लेबनान और इज़राइल का रिश्ता हमेशा संघर्ष, तनाव और राजनीतिक अस्थिरता से घिरा रहा है। दोनों देशों के बीच दशकों से चले आ रहे विवादों और सैन्य कार्रवाइयों ने क्षेत्र को हमेशा एक नाजुक संतुलन पर रखा है। लगभग एक साल तक चले सीमा तनाव, हिज्बुल्लाह और इज़राइली सेना के बीच झड़पों और हमला–प्रतिहमला के सिलसिले ने नवंबर 2024 में युद्धविराम के बाद थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन जमीन पर स्थिति अभी भी शांत नहीं है।

दक्षिण लेबनान, जो दशकों से इन टकरावों का केंद्र रहा है, आज भी इज़राइल की सैन्य मौजूदगी और हवाई हमलों का सामना कर रहा है। इन कार्रवाइयों ने स्थानीय आबादी में भय और असुरक्षा की भावना को गहरा किया है। प्रधानमंत्री सलाम का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह सिर्फ कूटनीति की भाषा नहीं, बल्कि उस जनता की पीड़ा और उम्मीदों की अभिव्यक्ति है जिसने लंबे समय से युद्ध और अस्थिरता का बोझ उठाया है।

सलाम ने यह भी साफ कहा कि किसी भी नई पहल पर विचार तभी किया जा सकता है, जब युद्धविराम समझौते का हर प्रावधान पूरी तरह लागू किया जाए। उन्होंने इज़राइल पर जोर दिया कि उसे दक्षिण लेबनान से अपनी सैन्य मौजूदगी समाप्त करनी चाहिए और हर तरह के हमले बंद करने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने हिज्बुल्लाह की जिम्मेदारियों की भी बात उठाई। समझौते के अनुसार हिज्बुल्लाह को निरस्त्रीकरण से जुड़े प्रावधानों का पालन करना होगा, हालांकि संगठन ने अपने हथियार पूरी तरह छोड़ने से इनकार किया है। हिज्बुल्लाह का तर्क है कि केवल राज्य को रक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार है, लेकिन उसने अपने अस्तित्व और भूमिका को सुरक्षा ढांचे के भीतर सीमित करने पर फिलहाल स्पष्ट सहमति नहीं दी है।

यह पूरी स्थिति बताती है कि लेबनान और इज़राइल के बीच शांति का रास्ता कितना लंबा और जटिल है। जमीन पर तनाव, राजनीतिक अविश्वास, क्षेत्रीय शक्तियों के प्रभाव और आंतरिक राजनीतिक विभाजन—हर चीज़ इस प्रक्रिया को कठिन बनाती है। प्रधानमंत्री सलाम जानते हैं कि आर्थिक सहयोग की संभावना मध्य-पूर्व में स्थिरता का एक बड़ा द्वार खोल सकती है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या दोनों पक्ष उस विश्वास और जिम्मेदारी को निभाने की स्थिति में हैं जो शांति की बुनियाद को मजबूत कर सके।

उनका यह बयान स्पष्ट संकेत देता है कि फिलहाल यह लक्ष्य काफी दूर दिखाई देता है। क्षेत्र में अभी भी हर दिन एक नई घटना, एक नया तनाव, एक नई अनिश्चितता जन्म लेती है। ऐसे माहौल में लेबनान आर्थिक सहयोग की किसी भी पेशकश को जल्दबाजी में स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है।

लोहा और जमीन कारोबारियों पर आयकर का शिकंजा छत्तीसगढ़ में एक साथ 24 ठिकानों पर छापेमारी

(जीएनएस)। रायपुर की सुबह आज सामान्य नहीं थी। सूरज निकलने से पहले ही शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में असामान्य हलचल बढ़ गई थी। उरला और सिलतरा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में अचानक गाड़ियों का काफिला दाखिल हुआ और देखते ही देखते आयकर विभाग की टीमें अलग-अलग फैक्ट्रियों, कार्यालयों और कोठियों के बाहर तैनात हो गईं। करीब सौ से अधिक सीआरपीएफ जवानों की मौजूदगी ने साफ कर दिया कि आज की कार्रवाई सामान्य नहीं, बल्कि एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है।

आयकर विभाग ने गुरुवार तड़के छत्तीसगढ़ के 24 प्रमुख प्रतिष्ठानों पर एकसाथ छापे शुरू किए। इन प्रतिष्ठानों में लोहा उद्योग, रियल एस्टेट कारोबार और एमएस पाइप निर्माण से जुड़े नाम शामिल हैं। प्रमुख रूप से सिलतरा स्थित इस्पात इंडिया के संचालक, आनंदम निवासी विनोद सिंगला के कई ठिकानों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया है। बताया गया कि सिंगला वर्षों से एमएस पाइप निर्माण के क्षेत्र में सक्रिय हैं और कारोबार का दायरा प्रदेश से बाहर भी फैला हुआ है।

उधर, रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े अरविंद

अग्रवाल—जिनका नाम सिग्नेचर होम्स से जुड़ा है—और उद्योगपति रवि बजाज—जिनके ठिकाने मैग्नेटो मॉल के पिछले हिस्से में स्थित हैं—वहीं ओम स्पंज के प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई की गई। इन सभी स्थानों पर आयकर विभाग की टीमों ने कई घंटे तक दस्तावेज़ खंगाले, कंप्यूटरों की हार्डड्राइव को सील किया और संदिग्ध लेनदेन से जुड़े कागजात जब्त किए।

छापेमारी का दायरा यह संकेत देता है कि विभाग को पहले से संग्रहीत कुछ इनपुट प्राप्त हुए थे, जिनके आधार पर यह व्यापक कार्रवाई की गई है। टीमों ने न सिर्फ वित्तीय लेन-देन वाले फाइलें देखीं, बल्कि स्टॉक रजिस्टर, बही-खाते और टैक्स से जुड़े रिकॉर्ड की भी गहन जांच शुरू कर दी है। यह भी बताया जा रहा है कि कुछ कंपनियों के बही-खातों और वास्तविक उत्पादन में अंतर की शिकायतें लंबे समय से विभाग के पास मौजूद थीं, जिनकी पुष्टि के लिए यह छापा अहम माना जा रहा है।

इन उद्योग क्षेत्रों में दिनभर किसी को अंदर-बाहर आने-जाने की अनुमति नहीं दी गई। कर्मचारी दफ्तरों के बाहर खड़े नजर आए और फैक्ट्री गेट पर सुरक्षा की व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा कड़ी दिखाई दी। कारोबार जगत में यह चर्चा तेज है कि आने वाले दिनों में कई और नाम इस जांच की चपेट में आ सकते हैं।

स्थानीय बाजारों में भी हलचल महसूस की जा रही है और उद्योग संघों ने भी इस कार्रवाई पर नजर बनाए रखी है।

देशभर में दूसरी बड़ी कार्रवाई—एनआईए की तड़के की रेड

उधर, ठीक इसी सुबह देश के तीन राज्यों—उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा—में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने भी एक बड़े अभियान को अंजाम दिया। अवैध गोला-बारूद की तस्करी से जुड़े एक संवेदनशील मामले की जांच करते हुए एनआईए ने कुल 22 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

यह छापेमारी तड़के शुरू हुई, जब एजेंसी की टीमों ने संदिग्ध ठिकानों को चारों ओर से घेर लिया। बताया जा रहा है कि यह मामला यूपी से बिहार के कई जिलों तक फैले एक नेटवर्क से जुड़ा है, जिसमें हथियार और गोला-बारूद की गैरकानूनी सप्लाई की आशंका जताई गई है। फिलहाल किसी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिन दस्तावेज़ों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एजेंसी ने कब्जे में लिया है, उनसे कई पर्दे उठने की उम्मीद जताई जा रही है।

एनआईए की ओर से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि विस्तृत जानकारी जांच की प्रगति के अनुसार साझा की जाएगी। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों का मानना है कि यह छापेमारी किसी बड़े नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में काफी अहम साबित हो सकती है।

सेना मानहानि मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत—सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2026 तक ट्रायल पर लगाई रोक, राजनीतिक हलकों में हलचल तेज

(जीएनएस)।नई दिल्ली की सर्द सुबह में सुप्रीम कोर्ट की गलियारों में आज एक बार फिर भारी भीड़ थी। कैमरों की फ्लैश लाइटें, पत्रकारों का जमा हुजूम और कानूनी रणनीतिकारों के बीच फुसफुसाहट—सब कुछ इस बात का संकेत दे रहा था कि आज होने वाली सुनवाई बेहद अहम है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय सेना पर कथित टिप्पणी को लेकर दर्ज मानहानि मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक और बड़ी राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक 22 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दी।

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ कहा कि अंतरिम सुरक्षा जारी रहेगी और इस अवधि में ट्रायल कोर्ट किसी भी तरह की आगे की सुनवाई नहीं करेगा। यह फैसला राहुल गांधी के लिए कानूनी ढाल की तरह है, जो आने वाले दो वर्षों तक कोर्ट की मौजूदगी से उन्हें बचाता रहेगा।

4 अगस्त की सुनवाई ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया था। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी के बयान पर तीखी टिप्पणी की थी और पूछा था कि चीन द्वारा "2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूमि कब्जे" का दावा किस तथ्य पर आधारित है। उन्होंने कहा था—

"एक सच्चा भारतीय इस तरह का बयान नहीं देगा। सीमा विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर ऐसी टिप्पणी देशहित में नहीं है।"

उसी दिन अदालत ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाई थी और उत्तर प्रदेश सरकार तथा शिकायतकर्ता से जवाब मांगा था। आज की सुनवाई उसी प्रक्रिया का आगे बढ़ना थी, जिसमें अब काफी लंबी राहत मिल गई है।

यह पूरा मामला सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव की शिकायत पर आधारित है। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर 2022 को भारत–चीन सीमा झड़प पर राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया था जिसमें कहा गया—चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जवानों की "पिटाई" कर रहे हैं और देश का मीडिया चुप है। इस बयान के बाद उनके खिलाफ समन जारी हुआ, जिसे राहुल गांधी ने चुनौती दे रखा है और उसे रद्द करवाने की कोशिश कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रायल स्थगित करने से यह मामला अब कम से कम डेढ़ साल तक आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसका सीधा राजनीतिक प्रभाव भी पड़ेगा—राहुल गांधी के लिए यह फैसला एक बड़ी रणनीतिक जीत माना जा रहा है, क्योंकि इस मामले की सुनवाई यदि जारी रहती, तो 2026 तक उन्हें लगातार अदालत के चक्कर लगाने पड़ सकते थे।

आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने न केवल उन्हें लंबी राहत दी, बल्कि कांग्रेस खेमे में राजनीतिक उत्साह भी बढ़ा दिया है।

अब अगली सुनवाई तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम ढाल के पीछे सुरक्षित है—और राजनीति में यह राहत आने वाले समय में एक बड़े संदेश के रूप में भी देखी जा रही है।

लैंड फॉर जॉब केस—फैसले का इंतजार फिर बढ़ा, लालू–राबड़ी–तेजस्वी अदालत में पेश नहीं, अब 8 दिसंबर को सुनाया जाएगा आदेश

(जीएनएस)। नई दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज सुबह माहौल हमेशा की तरह गंभीर था। सुरक्षाकर्मियों की चहल-पहल, मीडिया कैमरों की कतार और वकीलों के बीच हलचल पहले से ही यह संकेत दे रही थी कि सुनवाई का दिन महत्वपूर्ण है। बहुचर्चित लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में आरोप तय किए जाने को लेकर कोर्ट अपना आदेश सुनाने वाली थी, लेकिन एक बार फिर निर्णय टल गया।

स्पेशल जज विशाल गोगने ने स्पष्ट किया कि आदेश पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका था, परंतु सुनवाई के दौरान कुछ औपचारिक पहलुओं के पूरा न होने के कारण फैसला अभी स्थगित कर दिया गया है। अब अदालत यह निर्णय 8 दिसंबर को सुनाएगी कि आरोप तय किए जाएंगे या नहीं। इससे पहले भी 10 नवंबर को आदेश टल चुका है, और इस वजह से मामले में अनिश्चितता का दौर और लंबा हो गया है।

गुरुवार की सुनवाई में न तो लालू प्रसाद यादव मौजूद थे, न राबड़ी देवी और न ही तेजस्वी यादव। तीनों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने अदालत से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी, और कोर्ट ने इसे स्वीकार भी कर लिया।

कहना गलत न होगा कि इस केस की सुनवाई अब कानूनी दलीलों, तकनीकी बिंदुओं और अनुमति से जुड़े सवालों के इर्द-गिर्द घूमने लगी है।

लालू यादव की कानूनी टीम पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई की एफआईआर को रद्द करने की मांग रख चुकी है। यह भी तर्क दिया गया है कि सीबीआई ने आवश्यक सरकारी अनुमति, यानी प्रॉपर सैनक्शन, प्राप्त किए बिना जांच शुरू कर दी—इसलिए पूरी जांच ही अवैध है और ट्रायल नहीं चल सकता।

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने हाई कोर्ट में यह दलील देते हुए कहा कि "जब बुनियाद ही गलत है तो उस पर मुकदमा कैसे खड़ा हो सकता है।" हाई कोर्ट इस याचिका पर 25 सितंबर को सुनवाई करेगा। सीबीआई के वकील ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष इस बात पर नाराजगी जताई कि बचाव पक्ष जानबूझकर सुनवाई में देरी कर रहा है। एजेंसी का कहना है कि आरोप तय करने के चरण में लगातार तकनीकी दलीलें देकर प्रक्रिया को लंबा किया जा रहा है।

अदालत ने भी यह स्पष्ट किया कि प्रशासनिक अनुमति की बाध्यता भ्रष्टाचार निरोधक कानून (PC Act) के तहत दर्ज मामलों में लागू होती है, जबकि यह केस मुख्यतः आईपीसी की धाराओं के आधार पर दर्ज है—इसलिए अनुमति को आधार बनाकर पूरे ट्रायल को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता।

सीबीआई ने 7 अक्टूबर 2022 को पहली चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें लालू, राबड़ी, मीसा भारती सहित 16 लोगों को आरोपी बनाया गया। इसके बाद 25 फरवरी को कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया।

जून 2024 में अंतिम चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें कुल 78 लोगों को आरोपी बताया गया—इनमें रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 उम्मीदवार भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट पहले ही ट्रायल रोकने से इनकार कर चुका है, इसलिए अब पूरा ध्यान 8 दिसंबर की तारीख पर है। यही वह दिन होगा जब यह साफ होगा कि मामला आगे बढ़ेगा या बचाव पक्ष की आपत्तियाँ अदालत को रोक पाएँगी।

अभी हर किसी की निगाह इसी तारीख पर टिकी है—जहाँ से या तो इस केस की दिशा तय होगी या फिर एक और नया मोड़ सामने आएगा।

संपादकीय

'साथी' पर अविश्वास

हाल ही में केंद्र सरकार ने निर्देश दिए थे कि आगामी वर्ष मार्च से हर नये स्मार्टफोन में 'संचार साथी' ऐप पहले इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। दूसरी ओर पुराने स्मार्ट फोनों में इसे सॉफ्टवेयर अपडेट द्वारा भेजा जाएगा। जिसको लेकर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी और शीतकालीन सत्र में इसे बड़ा मुद्दा बनाया। विपक्ष का कहना था कि इससे निजता का उल्लंघन होगा और व्यक्ति के जीवन में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। विपक्ष ने इसे संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण व नागरिकों की निगरानी करने वाला टूल बताया। इस बहस के बीच विपक्ष को नया मुद्दा मिलते देख केंद्र सरकार ने अनिवार्य तौर पर ऐप प्री-इंस्टॉल करने का अपना फैसला वापस ले लिया। दरअसल, सरकार का कहना था कि डिजिटल होती दुनिया में लगातार बढ़ते साइबर अपराधों से नागरिकों को सुरक्षा देने के मकसद से यह पहल की गई थी। उसका कहना था कि लगातार जटिल होते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिये ऐसी पहल अपरिहार्य है। लेकिन विपक्ष का आरोप था कि साइबर अपराधों के खिलाफ सुरक्षा के नाम पर सरकारी हस्तक्षेप से नई तरह की असुरक्षा पैदा हो सकती है। बताया जाता है कि सरकार ने स्मार्टफोन में साइबर सुरक्षा ऐप इस तरह इंस्टाल करने को कहा था ताकि उसे डिलीट या अक्षम न किया जा सके। केंद्र की दलील थी कि यह ऐप उपभोक्ता को धोखाधड़ी वाले फोन और संदेशों की रिपोर्ट लिखवाने में मदद करता। साथ ही चोरी किए गए मोबाइल की बरामदगी आसान हो पाती। लेकिन निजी डेटा सुरक्षा व इसकी कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए गए, जिसके चलते इसका विरोध हुआ। वैसे सर्च इंजन में पहले से मौजूद इस ऐप को देश के लाखों लोग पहले ही स्वेच्छा से डाउनलोड कर चुके हैं। लेकिन इसको अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करने के आदेश के बाद विरोध के स्वर उभरने लगे। जिसके बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि इसके जरिये व्यक्ति की निजता का अतिक्रमण करके उसके जीवन में ताक-झांक की जा सकती है।

हालांकि, विरोध के सुर मुखर होने के बाद सरकार की ओर से स्पष्टीकरण आया कि यह निर्णय वैकल्पिक है और कोई व्यक्ति इस ऐप को इच्छानुसार डिलीट कर सकता है। निस्संदेह, निजता हमारा मौलिक अधिकार है। ऐसे में किसी ऐप की अनिवार्यता से व्यक्ति की गोपनीयता में खलल पड़ने की आशंका जतायी जाने लगी। पिछले दिनों सरकार ने व्हाट्स ऐप व टेलीग्राम आदि कम्युनिकेशन ऐप्स संचालक कंपनियों से कहा था कि वे अपनी सेवा को मोबाइल के सिम कार्ड से जोड़कर रखें। ताकि सिम के बिना इन ऐप का दुरुपयोग न हो सके। जिसको लेकर टेलि-कम्युनिकेशन कंपनियों ने सकारात्मक प्रतिसाद दिया था। निस्संदेह, निजता का अधिकार देश में मौलिक अधिकार के रूप में मौजूद है। शीर्ष अदालत ने भी अपने एक निर्णय के जरिये स्पष्ट किया था कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 21 में 'राइट टू प्राइवेसी' में भी निहित है। जिसके अंतर्गत मोबाइल, इंटरनेट व डिजिटल जानकारियां भी शामिल हैं। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से इतर व्यक्ति को अपनी डिजिटल संप्रभुता की सुरक्षा का हक है। यही वजह है कि विगत में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मोबाइल व निजी कंपनियां उपभोक्ता से आधार कार्ड नहीं मांग सकती। इस फैसले को तब निजता की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया था। यही वजह है कि 'संचार साथी' की अनिवार्यता के बाद निजता व व्यक्ति के डेटा में सरकारी दखल को लेकर सवाल उठने लगे। निस्संदेह, आज के डिजिटल युग में व्यक्ति का डेटा बेहद महत्वपूर्ण है। जिसकी हर कीमत पर सुरक्षा की जानी चाहिए। वहीं इसके साथ ही इस बात की भी पड़ताल होनी चाहिए कि कहीं कुछ अन्य ऐप हमारे डेटा में तो सेंध नहीं लगा रहे हैं? सरकार को इससे उपभोक्ता की सुरक्षा करनी होगी। वहीं तर्क दिया जा रहा है कि संचार साथी ऐप को अनिवार्य करने के बजाय आम लोगों को नई तकनीक और इसके इस्तेमाल के लिये सतर्क करने को देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। साथ ही इसके लिये आम जनता को प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। जिससे तकनीक के जरिये साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाने की मुहिम को गति दी जा सके।

निहित स्वार्थों के लिए युवाओं को गुमराह करने के बयान

> गौरतलब है कि दिल्ली के लाल किले के पास विस्फोट की जांच कर रहे जांचकर्ताओं ने खुलासा किया था कि जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े डॉक्टरों से जुड़े संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल ने 6 दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छह स्थानों पर विस्फोटों की योजना बनाई थी। यह वह दिन था जब 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था।

जमीयत उलमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने भोपाल में एक कार्यक्रम में कहा कि आज मुसलमान रास्ते पर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें कदम-कदम पर नफरतों का सामना करना पड़ता है। मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठाते हुए कहा कि किसी देश में लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम-फ्री समाज बनाना इंसाफ के बिना नामुमकिन है। मौलाना ने कहा कि दुख की बात है कि पिछले कुछ सालों में खासकर बाबरी मस्जिद और ट्रिपल तलाक जैसे मामलों में फैसलों के बाद यह आम सोच बन गई है कि कोर्ट सरकारी दबाव में काम कर रहे हैं। राजनीतिक दल और मदनी जैसे मौलाना मुसलमानों में अपनी पैठ बनाने और खुद को उनका सबसे बड़ा हितेषी साबित करने में कहीं न कहीं मुस्लिम युवाओं को गुमराह कर रहे हैं।गौरतलब है कि दिल्ली के लाल किले के पास विस्फोट की जांच कर रहे जांचकर्ताओं ने खुलासा किया था कि जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े डॉक्टरों से जुड़े संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल ने 6 दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छह स्थानों पर विस्फोटों की योजना बनाई थी। यह वह दिन था जब 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था। विस्फोट के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकवादियों ने बताया था कि यह तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि वे बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेना चाहते थे। मौलाना मदनी का बयान ऐसे ही युवाओं को प्रेरित कर गुमराह करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने वाले मौलाना मदनी भूल गए कि अदालतों ने ही आतंक के आरोपों से ढेरों बेगुनाहों को बरी किया है। वर्ष 2006 में 12 लोगों को मुंबई बम धमाकों के संबंध में मकोका कोर्ट ने दोषी ठहराया था, लेकिन 18 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। कोर्ट ने पाया कि पुलिस द्वारा पेश किए गए 44,500 पन्नों के दस्तावेज़ों में से कोई भी दोष सिद्ध नहीं कर सका। इसी तरह

गुजरात में 2001 में 127 मुस्लिम नागरिकों को एक प्रतिबंधित संगठन से संबंध के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जो 19 साल बाद बरी हुए थे। इसके अलावा ऐसे एकल मामलों की कमी नहीं है, जब अदालतों ने जांच एजेंसियों की कार्रवाई को अपर्याप्त मानते हुए आतंक के आरोपियों को बरी किया।

मुस्लिम हितों की बात करने वाले मौलाना मदनी भूल गए कि यह वही सुप्रीम कोर्ट है, जिसने केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड कानून को ज्यों का त्यों लागू करने पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई। विशेष रूप से कोर्ट ने वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होने की शर्त और विवादित संपत्तियों के तुरंत वक्फ माने जाने पर रोक लगा दी। यह फैसला याचिकाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और मामले में संतुलन बनाए रखने के लिए एक अंतरिम रोक है। देश की करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को तलाक का कानूनी हक दिलाने वाले सुप्रीम कोर्ट को मौलाना मदनी भूल गए। मनमाने तरीके से तलाक की शिकार महिलाओं को उनका हक दिलाने की पहल किसी भी मौलवी—मौलाना ने कभी नहीं की।

अकेले मौलाना मदनी ही नहीं राजनीतिक फायदे के लिए राजनीतिक दलों के नेता भी मुसलमानों के भले के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते रहे हैं। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने लाल किले के सामने हुई ब्लास्ट पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर का गुस्सा अब लाल किले पर दिख रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एक व्यक्ति के अपराध की सजा पूरे जम्मू-कश्मीर के लोगों को नहीं दी जा सकती। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अपील की है कि वे इस गंभीर विषय पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बात करें क्योंकि राज्य के बाहर रहने वाले कश्मीरी डरे हुए हैं। महबूबा का यह बयान कहीं न कहीं दिल्ली की वारदात को जायज ठहराने का प्रयास है। महबूबा सत्ता पाने के लिए पूर्व में भी ऐसे विवादित बयान देती रही हैं। महबूबा ने कहा था साल 2019 में धारा 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में "डर और घुटन का माहौल" है। गिरफ्तारियां हो रही हैं और लोगों पर दबाव है

इससे पहले जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ऐसा ही बयान दिया, जिससे कहीं न कहीं आतंकवादियों और उनके पनाहगारों के प्रति सहानुभूति छिपी हुई थी। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने दिल्ली में आत्मघाती हमलावर के परिवार के घर को गिराए जाने पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम सिर्फ गुस्सा बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा अगर आतंकवाद ऐसे कामों से रुक जाता, तो यह बहुत पहले ही खत्म हो गया होता। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद हाल ही में कम हुआ है, "किसी का घर उड़ाने की ज़रूरत के बिना"। सुरक्षा तीन नियंत्रित विस्फोट करके दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के कोइल गांव में डॉ. उमर उन नबी के दो मंजिला घर को ध्वस्त कर दिया था।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने गांदरबल जिले में गैर-स्थानीय मजदूरों पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा में एक्स पर अपने पोस्ट में आतंकी शब्द का जिक्र नहीं किया। इसी तरह पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी अपने पोस्ट में आतंकी शब्द से परहेज किया। इस आतंकी हमले में 7 की जान चली गई थी। विपक्षी दलों ने मुस्लिम आतंकी हो या गैंगस्टर, यही प्रयास किया है कि इनके साथ नरमी बरती जाए। जाहिर कारण है मुस्लिम वोट बैंक। विपक्षी दलों को लगता है कि इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने से मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा।

सत्ता में आने के बाद पंजाब की मान सरकार ने दावा किया था कि तत्कालीन पंजाब सरकार ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को यूपी सरकार से बचाने के लिए 55 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किए थे। मुख्तार को आरामतलब जिंदगी देने के लिए वो सारी व्यवस्थाएं की गई थीं जो कि एक हाईप्रोफाइल को मिलती हैं। इतना ही नहीं तत्कालीन पंजाब सरकार ने भरसक कोशिश की अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश नहीं भेजा जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। कोर्ट के आदेश से अंसारी की वापसी उत्तर प्रदेश हो सकी। इन उदाहरणों से जाहिर है कि राजनीतिक दल वोट बैंक बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे उनकी हरकतों से युवा गुमराह ही क्यों न हो जाएं। आश्चर्य की बात यह है कि मदनी जैसे मौलाना हों या फिर राजनीतिक दल यह भूल गए कि ऐसी तमाम हरकतों को देश के मतदाता कई बार नकार चुके हैं।

प्रेरणा

ज्ञान की तपस्या और आत्मबोध का ज्योतिर्मय पथ

पंजाब के गुजरांवाला जिले के शांत और सरल से प्रतीत होने वाले मुरारीवाला ग्राम में एक ऐसा बालक जन्मा, जिसकी प्रतिभा ने आगे चलकर न केवल शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए, बल्कि आध्यात्मिक दुनिया को भी नई दिशा प्रदान की। यह वही बालक था—रामतीर्थ—जिसकी आंखों में बचपन से ही ज्ञान का प्रकाश चमकता था। उसकी अध्ययन-निष्ठा और आत्मिक जिज्ञासा इतनी तीव्र थी कि वह साधारण वातावरण में रहते हुए भी असाधारण उपलब्धियों की ओर बढ़ता चला गया।

सन 1891 में जब उसने पंजाब विश्वविद्यालय की बी.ए. परीक्षा पूरे प्रांत में प्रथम स्थान से उत्तीर्ण की, तो शिक्षा जगत में उसकी मेधा की चर्चा होने लगी। उसे दस रुपये मासिक की छात्रवृत्ति मिली, जो उस समय न केवल एक सम्मान था, बल्कि उसकी प्रतिभा की आधिकारिक स्वीकृति भी थी। अध्ययन उसके लिए केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं था; वह उसके लिए एक तपस्या थी। इसी तपस्या की शक्ति से उसने एम.ए. की परीक्षा भी सर्वोच्च अंकों के साथ उत्तीर्ण की और फिर उसी कॉलेज में गणित के प्रोफेसर नियुक्त हुए।

लेकिन ज्ञान केवल पाठ्यपुस्तकों में सीमित नहीं होता—यह बात रामतीर्थ ने बहुत जल्दी समझ ली थी। गणित के सूत्रों और सिद्धांतों के बीच, जीवन का वास्तविक समीकरण उन्हें कुछ और ही दिशा में खींच रहा था। धीरे-धीरे उनके भीतर वैराग्य का बीज अंकुरित होने लगा। दुनिया की भौतिक उपलब्धियाँ उन्हें सफल तो बना सकती थीं, परंतु संतुष्ट नहीं। उनके भीतर का साधक जाग रहा था—एक ऐसा साधक जो सत्य के अंतिम स्रोत की खोज के लिए भीतर की यात्रा करना चाहता था।

1901 में उन्होंने अचानक लाहौर छोड़ दिया और टिहरी गढ़वाल के कोटी ग्राम की ओर प्रस्थान किया। वहां, एक शाल्माली वृक्ष के नीचे उन्होंने ईश्वरीय साधना आरंभ की। प्रकृति की गोद में, शांत पहाड़ों के बीच बैठकर जब उन्होंने ध्यान साधना की, तो प्रोफेसर रामतीर्थ धीरे-धीरे स्वामी रामतीर्थ बनकर उभरने लगे। उनका व्यक्तित्व अब केवल एक विद्वान या आचार्य का नहीं, बल्कि एक तपस्वी, एक साधक, एक ज्ञानी का था, जिसकी दृष्टि संसार से अधिक आत्मा के भीतर के प्रकाश को देखने लगी थी।

उसी समय टिहरी रियासत के राजा कीर्तिशाह, जो अपने नास्तिक विचारों के लिए प्रसिद्ध थे, स्वामी रामतीर्थ से वाद-विवाद के उद्देश्य से आए। वे तर्क की कसौटी पर आस्था को परखना चाहते थे, परंतु उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जिसके सामने वे बैठे हैं, वह केवल एक धर्मोपदेशक नहीं, बल्कि एक ऐसे जानकार हैं जिनके शब्दों में शांति है, whose logic is not loud but luminous. स्वामी रामतीर्थ की शांत मुद्रा, उनके ज्ञान की गहराई और उनके तर्क की पवित्रता ने राजा की सारी शंकाओं को उसी क्षण ध्वस्त कर दिया। वह राजा, जो स्वयं को नास्तिक कहने में गर्व महसूस करता था, स्वामी रामतीर्थ के चरणों में गिर पड़ा। उसके भीतर आस्था की ज्योति प्रज्वलित हो चुकी थी।

राजा ने स्वामी रामतीर्थ का इतना सम्मान किया कि उन्हें जापान में आयोजित होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में भेजा। वहाँ भारत की आध्यात्मिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वामी रामतीर्थ ने अपनी वाणी, अपने विचार और अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। वे केवल गणितज्ञ नहीं रहे; वे अब एक आध्यात्मिक दूत, एक समाज सुधारक, एक देशभक्त, और एक तत्वज्ञ बन चुके थे। उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान वह है जो भीतर के प्रकाश को प्रकट करे और मानवता को जोड़ने का सामर्थ्य रखे।

समय बीतता गया और उनके भीतर का साधक अपने अंतिम लक्ष्य की ओर अग्रसर होता गया। दीपावली के पावन दिन, जब जगत दीपों से जगमगाता है, स्वामी रामतीर्थ ने गंगा नदी में जलसमाधि लेकर अपनी देह-यात्रा का अंत किया। वह अंत नहीं, बल्कि उनके लिए परम मुक्त‍ि का क्षण था—जहाँ ज्ञान, साधना और आत्मबोध एक होकर ब्रह्म में विलीन हो गए।

स्वामी रामतीर्थ आज भी केवल एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं हैं; वे एक प्रेरणा हैं—उस पथ की, जहाँ संसार की चमक से परे, आत्मा का अनंत प्रकाश चमकता है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि ज्ञान की वास्तविक जीत तब होती है जब मनुष्य अपने भीतर के सत्य से जुड़ जाता है।

पुतिन की भारत यात्रा: नयी विश्व राजनीति की आहट

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा एक साधारण कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि इतिहास के सात दशकों में बुनी एवं गढ़ी गई मित्रता का नवीन उद्घोष है। कहा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्थायी मित्र और शत्रु नहीं, स्थायी हित होते हैं, किंतु भारत-रूस संबंध इस कथन की परिधि से आगे जाकर स्थायी भरोसे, नैतिक दायित्व और पारस्परिक सम्मान के प्रतीक बने हुए हैं। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब पश्चिमी देश विशेषकर अमेरिका, यूरोप एवं नाटो गठबंधन रूस पर कठोर आर्थिक और रणनीतिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इसके बावजूद भारत ने रूस को न केवल कूटनीतिक स्तर पर सम्मान-साथ दिया बल्कि ऊर्जा व रक्षा क्षेत्र में उसे सबसे भरोसेमंद साझेदार माना। इसलिए यह वार्ता केवल दो नेताओं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एवं भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मुलाकात नहीं, बल्कि एक नए युग के सूत्रपात का संकेत है, नयी विश्व राजनीतिक समीकरण की आहट है।भारत और रूस की मित्रता का इतिहास लगभग 70 वर्षों का है। शीतयुद्ध काल में रूस (तत्कालीन सोवियत संघ) ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की संप्रभुता और सुरक्षा हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से लेकर पोखरण परमाणु परीक्षणों तक, रूस ने भारत का साथ दिया। आज जब यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक राजनीति को ध्रूवीकृत कर दिया है, अमेरिका ने भारत पर रूस से दूरी बनाने का दबाव बनाया, किंतु भारत ने सामरिक स्वायत्तता की नीति को बनाए रखते हुए रूस का साथ निभाया। पश्चिम के प्रतिबंधों के बीच भारत ने भारी मात्रा में रूसी पेट्रोलियम और गैस खरीदकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की तथा रूस को आर्थिक सहारा दिया। यह निर्णय महज एक वाणिज्यिक लाभ का मामला नहीं था, बल्कि भारतीय विदेश नीति की स्वयंभूता का प्रदर्शन था। दूसरी ओर, रूस ने भी भारत को कभी निराश नहीं किया। चाहे एस-400 वायु रक्षा प्रणाली हो, टी-90 टैंक हों, ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना हो या पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुयू-57 से जुड़ा सहयोग, भारत की सैन्य क्षमता में रूस का योगदान निर्णायक रहा है। वहीं पाकिस्तान की शत्रुता के खिलाफ भारत के हितों को रूस का अप्रत्यक्ष समर्थन मिलता रहा। हाल ही में दक्षिण एशिया की बदलती सुरक्षा परिस्थितियों में रूस ने भारत की सामरिक चिंता को समझा और 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे अभियानों में सहयोग की भूमिका निभाई। यह तथ्य भारत-रूस संबंधों की गहराई और विश्वास को दर्शाता है। पुतिन और मोदी की वार्ता ऐसे समय आयोजित हो रही है, जब वैशिक शक्ति-संतुलन परिवर्तन के दौर में है। अमेरिका-चीन तनाव, यूक्रेन युद्ध, पश्चिमी प्रतिबंध, ऊर्जा बाजारों की अस्थिरता और पश्चिमी देशों की रूस के विरुद्ध एकजुटता, इन परिस्थितियों में भारत की भूमिका मध्यस्थ, संतुलक तथा स्वतंत्र धुरी के रूप में उभर रही है। पुतिन भारत को न केवल रक्षा सहयोगी मानते हैं, बल्कि एशियाई भू-राजनीति में संतुलन का स्तंभ भी। वहीं मोदी की विदेश नीति बहुध्रूवीय विश्व की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें रूस का स्थान केंद्रीय है।

इस यात्रा से ऊर्जा सहयोग और बढ़ेगा। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है और रूस उसके लिए सस्ता, विश्वसनीय तथा दीर्घकालिक आपूर्तिकर्ता। प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने भारत को कच्चे तेल के साथ ही कोयला, गैस और परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में सहयोग दिया। भारत को सस्ती ऊर्जा देने के पीछे केवल व्यावसायिक हित नहीं बल्कि मित्रता और सामरिक साझेदारी भी निहित है। रक्षा क्षेत्र में सहयोग और विस्तृत होने की उम्मीद है। भारत का लक्ष्य 'मेक इन इंडिया' रक्षा उत्पादन है और रूस इसके लिए सबसे बड़ा भागीदार बना हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल, राइफल निर्माण, स्पेयर पार्ट सप्लाई और संयुक्त विकास कार्यक्रमों के नए विकल्प वार्ता में उभरेंगे। रूस भारत को केवल उपभोक्ता नहीं, निर्माता के रूप में स्थापित करने में सहभागी है, जो संबंधों की परिपक्वता को दर्शाता है।

भारत-रूस दोस्ती अब एक नया अध्याय लिखने को तत्पर है। दोनों देशों की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है, यहां तक की अमेरिका के साथ बेहतर हुए संबंधों के दौर में भी रूस हमारा विश्वस्त साझीदार बना रहा है, प्रगाढ़ दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से दोनों देशों की दोस्ती में नई गरमाहट की संभावना के साथ दोस्ती के नये स्वस्तिक उकेरने की बात सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के वर्षों में अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है, लेकिन रूस के साथ देश के दशकों पुराने रक्षा संबंध भी बरकरार हैं। भारत ने अमेरिका और यूरोप से हथियारों की खरीद बढ़ाकर रूस पर निर्भरता को संतुलित बनाया है, लेकिन मॉस्को अभी भी भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। रूस दोस्ती की ओर आगे बढ़ते हुए भारत के लोगों को रोजगार देने के लिये भी एक समझौता मसौदा तैयार किया है। रूस अपने उद्योगों के लिए 10 लाख भारतीय कुशल श्रमिकों को काम पर रखना चाहता है।

भारत-रूस संबंधों का सबसे मजबूत आधार है-कूटनीतिक विश्वास और सम्मान। रूस ने कभी भारतीय आंतरिक राजनीति या नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। उसने कश्मीर, परमाणु नीति, रणनीतिक साझेदारी और पड़ोसी विवादों पर भारत की संप्रभुता का समर्थन किया। वहीं भारत ने भी रूस की सुरक्षा चिंताओं को समझाकृचाहे नाटो विस्तार का मुद्दा हो या यूक्रेन का संघर्ष। इसलिए भारत ने पश्चिमी दबावों की उपेक्षा करते हुए संवाद और शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की। अंतरिक्ष विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, अनुसंधान और चिकित्सा के क्षेत्र में भी रूस की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में रूस सहयोगी रहा है और भविष्य की यात्री-वाहक मिशनों में भी सहयोग की संभावनाएँ हैं। दोनों देशों की सांस्कृतिक साझेदारी भी विशेष हैरू योग, आयुर्वेद, साहित्य, रूसी नाट्यकला और भारतीय कलाकृसबने एक-दूसरे समाज में स्थान पाया। फिर भी यह संबंध चुनौतियों से खाली नहीं। चीन-रूस साझेदारी और भारत-अमेरिका निकटता के बीच संतुलन बनाए रखना दोनों देशों के लिए चुनौतीपूर्ण है।

अभियान

त्रिदेव के दिव्य अवतार, प्रकृति के शाश्वत गुरु और आत्मज्ञान की अनंत साधना की अद्भुत कथा

दत्तात्रेय जयंती भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का वह पावन पर्व है जिस पर केवल देवत्व ही नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, साधना, प्रकृति और गुरु-परंपरा की असाधारण महिमा एक साथ प्रत्यक्ष होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह दिन हजारों वर्षों से साधकों, योगियों, तपस्वियों और भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। यह तिथि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान मात्र नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर उतरने, अपनी चेतना को समझने और जीवन के गहरे अर्थ को अनुभव करने का अवसर है। दत्तात्रेय जयंती का हर क्षण व्यक्ति को यह स्मरण कराता है कि दिव्यता कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके ही भीतर निवास करती है।

पुराणों के अनुसार भगवान दत्तात्रेय त्रिदेव—ब्रह्मा, विष्णु और महेश—के संयुक्त अवतार हैं। यह कथानक उतना ही दिव्य है जितना अद्वितीय। ऋषि अत्रि और देवी अनसूया के घर में जन्मे दत्तात्रेय की उत्पत्ति स्वयं प्रकृति के नियमों की तरह शाश्वत और रहस्यमय है। एक कथा के अनुसार, त्रिदेव देवी अनसूया की पतिव्रता शक्ति की परीक्षा लेने उनके आश्रम पहुँचे। अनसूया की महान

तपस्या और पवित्रता से प्रसन्न होकर वे एक ही रूप में प्रकट हुए और दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया। इसीलिए दत्तात्रेय को "त्रिगुणात्मक पुरुष" कहा जाता है—जो सृष्टि, पालन और संहार जैसे तीनों ही दिव्य गुणों का समन्वित रूप हैं।

दत्तात्रेय का चरित्र भारतीय योग-परंपरा का ऐसा स्तंभ है जिस पर अध्यात्म, संयम, भक्ति, ज्ञान और त्याग जैसे सभी गुणों की नींव रखी गई है। उन्हें योगियों का गुरु और गुरु-परंपरा का आदि गुरु माना जाता है, क्योंकि उनका जीवन किसी एक स्थान या एक नियम में बंधा नहीं था। वे भिक्षाटन में, योग-साधना में, वन्य प्रदेशों में, पर्वतों में, शांत नदी किनारों पर और प्रकृति की गहराई में विचरण करते हुए स्वयं को निरंतर साधते रहे। उनका मार्ग संसार से दूर जाने का नहीं, बल्कि संसार को भीतर समाहित कर, उसमें रहने वाली परम शांति को पहचानने का था।

उनके जीवन का सबसे महान संदेश वह है जिसे "24 गुरु" कहा जाता है। दत्तात्रेय ने इस जगत के हर तत्व—पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, चंद्रमा, सूर्य, पर्वत, नदी, पशु-पक्षी, कीट-पतंग, समुद्र, कमल, सर्प और यहां तक कि साधारण वृक्षों से भी जीवन के रहस्य सीखे। उनके लिए पूरा ब्रह्मांड एक खुली आध्यात्मिक पाठशाला था। वे कहते थे कि सीखना तब शुरू होता है जब मनुष्य अहंकार छोड़ देता है और प्रकृति को अपना गुरु स्वीकार कर लेता है। उनके अनुसार, यदि मनुष्य खुला मन रखे तो हर घटना, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति उसके जीवन का शिक्षक बन सकती है।

दत्तात्रेय जयंती के दिन भक्त व्रत रखते हैं, मन को शांत करते हैं और "ॐ द्रम दत्तात्रेयाय नमः" मंत्र का जाप करते हैं। यह मंत्र मन की अशांति को दूर कर शांति और स्थिरता प्रदान करने वाला माना जाता है। दत्तात्रेय चालीसा और दत्त स्तोत्र का पाठ भक्त को वैराग्य, ज्ञान और शक्ति से भरते हैं। अनेक लोग पूरे दिन ध्यान में लीन रहते हैं ताकि भीतर की आवाज़ सुनी जा सके जिसे सामान्य दिनों की भागदौड़ में हम अक्सर अनसुना कर देते हैं।

भारत के कई तीर्थों पर इस दिन विशेष आयोजन होते हैं। गुजरात का गिरनार पर्वत, महाराष्ट्र का औंढा नागनाथ मंदिर, आंध्र प्रदेश का पिथापुरम और कर्नाटक का नारायणपुर—ये सभी स्थान उस दिव्य ऊर्जा से भर उठते हैं जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। हजारों साधक और भक्त इन स्थानों पर एकत्र होते हैं, मानो समस्त वातावरण ही दिव्यता की तरंगों से भर गया हो। हर तरफ दीपों की रोशनी, मंत्रों की ध्वनि, भजन-कीर्तन की गूंज और साधकों की ध्यानमग्न मुद्रा इस पर्व को आध्यात्मिक आस्था का चरम अनुभव बना देती है।

दत्तात्रेय जयंती केवल पूजन का दिन नहीं, बल्कि आत्मावलोकन का भी अवसर है। यह व्यक्ति को यह एहसास कराती है कि जीवन का वास्तविक सुख बाहरी भोगों में नहीं, बल्कि भीतर की मौन शांति में छिपा है। दत्तात्रेय का मार्ग मनुष्य को यह सिखाता है कि इच्छाओं की भीड़ जितनी कम होगी, मन उतना ही हल्का होगा। संसार की आपाधापी में भटकता व्यक्ति इस दिन ठहरकर यह समझ सकता है कि सच्चा गुरु वह है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश दिखाता है। यह गुरु बाहरी भी हो सकता है, और भीतर भी। दत्तात्रेय जयंती हमें यह भी याद दिलाती है कि प्रकृति का हर रंग, हर लय, हर परिवर्तन अपने भीतर कोई न कोई गहरा संदेश छिपाए हुए है। यदि हम उसे समझने का प्रयास करें, तो जीवन एक निरंतर सीखने की यात्रा बन जाता है। दत्तात्रेय का जीवन यह स्वीकार करता है कि मनुष्य चाहे कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, प्रकृति हमेशा उससे कई कदम आगे ही रहती है। इसलिए उसके साथ संवाद करना, उसे प्रणाम करना और उससे सीखना ही मनुष्य के लिए वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है।

यह पर्व व्यक्ति को यह संदेश देता है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि स्वयं को जानना है—अपनी चेतना, अपनी शक्ति, अपने उद्देश्य और अपनी दिशा को पहचानना है। दत्तात्रेय जयंती मनुष्य को भीतर के प्रकाश की पहचान कराती है और उसे उस दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है जहाँ शांति, संतोष, ज्ञान और दिव्यता एक साथ मिलते हैं। यही कारण है कि यह पर्व सदियों से साधना, भक्ति, त्याग और आत्मज्ञान का प्रतीक बनकर आज भी उतनी ही श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है जितना प्राचीन काल में।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कच्छ के धोरडो से रणोत्सव 2025-26 का शुभारंभ कराया

▸▸ धोरडो में रणोत्सव में 'एकत्व – एक देश, एस गीत, एक भावना' की संस्कृति को उजागर करने वाली कृतियों का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ

▸▸ मुख्यमंत्री ने कच्छ के पर्यटन को गति देने के लिए लखपत किलो, तेरा हेरिटेज विलेज तथा धोरडो के 179 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का ई-लोकार्पण तथा शिलान्यास किया

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- ▸▸ प्रधानमंत्री की प्रेरणा से शुरू हुआ रणोत्सव आर्थिक-सामाजिक विकास का श्रेष्ठ उदाहरण तथा ग्लोबल इवेंट बना है
- ▸▸ समाज, संस्कृति एवं समृद्धि के संगम से रचा गया 'धोरडो मॉडल' विश्वभर के विशेषज्ञों के लिए एक केस स्टडी
- ▸▸ रणोत्सव में परंपरागत कच्छी भूंगा तथा आधुनिक टैंट सिटी से प्रधानमंत्री का 'विकास भी, विरासत भी' का दृष्टिकोण साकार हुआ
- ▸▸ रणोत्सव में पर्यटकों की सुविधा के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की राज्य सरकार की मंशा

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को सफेद रेगिस्तान धोरडो से कच्छ रणोत्सव 2025 का शुभारंभ कराते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का कच्छ के रण (रेगिस्तान) को पर्यटन का तोरण (वंदनवार) और विश्व के लिए फेवरेट टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने का सपना साकार हुआ है। इस संदर्भ में श्री पटेल ने जोड़ा कि रणोत्सव अब ग्लोबल इवेंट बन गया है और प्रधानमंत्री की प्रेरणा से समाज, संस्कृति एवं समृद्धि के संगम से रचा गया धोरडो मॉडल विश्वभर के विशेषज्ञों के लिए केस स्टडी बना है।
मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम् के 150 वर्ष होने के अवसर को जोड़ने वाले 'एकत्व – एक देश, एक गीत, एक भावना' थीम आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों, कच्छी कला तथा गुजरात की संस्कृति को उजागर करने वाली कृतियों के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ रणोत्सव का उद्घाटन किया।
उन्होंने कच्छ के पर्यटन को गति देने के लिए लखपत किला, तेरा हेरिटेज विला और धोरडो के 179 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का ई-लोकार्पण तथा शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री कुँवरजीभाई बावळिया तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री त्रिकमभाई छांगा उपस्थित थे।
श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी ने रणोत्सव की शुरुआत कराते हुए कहा था, 'एक दिन दुनियाभर से पर्यटक धोरडो आएँगे और कच्छ की संस्कृति को आनंद उठाएंगे।' प्रधानमंत्री का बात सत्य सिद्ध हुई है।
उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (डब्लूएनटीओ) ने धोरडो को 'बेस्ट टूरिज्म विलेज' के अवॉर्ड से नवाजा है। कच्छी भूंगा (झोंपड़ी) और कच्छ की विविधतापूर्ण लोक संस्कृति के साथ आधुनिक सुविधा से युक्त टैंट सिटी से प्रधानमंत्री का 'विकास भी, विरासत भी' का दृष्टिकोण साकार हुआ है।
कच्छ रणोत्सव से गुजरात के पर्यटन उद्योग को गति मिलने के साथ रणोत्सव को अनेक लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का माध्यम बताते हुए श्री पटेल ने कहा कि रणोत्सव में लाखों सैलानियों के आने के कारण परंपरागत कलाकृतियों को वैश्विक बाजार मिलने के साथ ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण एवं स्थानीय हस्तकला कारीगरी की वस्तुओं और 'वोकल फॉर लोकल' तथा 'लोकल फॉर ग्लोबल' को वेग मिला है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत तथा देश की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पर्यटन स्थलों के विकास के लिए ओवरऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया है। पर्यटन के विकास के लिए कच्छ सहित समग्र गुजरात में उत्तम इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है और उसका लाभ पर्यटन गतिविधियों तथा विशेषकर रणोत्सव को मिल रहा है। श्री पटेल ने पर्यटकों की सुविधा के लिए और अधिक से अधिक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की राज्य सरकार की मंशा व्यक्त की।
उन्होंने कहा कि सफेद रण तक पर्यटक सरलता से पहुँच सकें; इसके लिए उत्तम सड़क मार्ग, बस कनेक्टिविटी, भुज तक रेल एवं एयर कनेक्टिविटी, भुज तक रेल एवं एयर कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री के विजन से मिली है। इससे पर्यटकों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। गत रणोत्सव में 10 लाख से अधिक पर्यटकों ने सफेद रेगिस्तान का आनंद उठाया है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर नागरिकों से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत@2047 के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध होने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने इस संकल्प को साकार करने के लिए पर्यटन क्षेत्र को अग्रसर बनाकर विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की।
धोरडो में मुख्यमंत्री ने सफेद रण की सैर करते हुए रेगिस्तान के सौंदर्य से युक्त सूर्यास्त का नजारा देखा। श्री पटेल ने धोरडो में सरदार वल्लभभाई पटेल के अखंड भारत, एक भारत के विजन को जन-जन तक पहुँचाने की भावना को चरितार्थ करने वाले सरदार स्मृतिवन का लोकार्पण भी किया।
इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की रंगांरग प्रस्तुति हुई।
कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री जनकसिंह जाडेजा, विधायक सर्वश्री केशूभाई पटेल, प्रद्युमनसिंह जाडेजा, अनिरुद्धभाई दवे, पर्यनट विभाग के सचिव श्री राजेन्द्र कुमार, कच्छ जिला कलेक्टर श्री आनंद पटेल, जिला विकास अधिकारी श्री उत्सव गौतम, जीएलपीसी के प्रबंध निदेशक श्री सुधीर पटेल, गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड (टीसीजीएल) के प्रबंध निदेशक श्री प्रभव जोशी, अग्रणी श्री देवाभाई देवजीभाई वरचंद, धोरडो ग्राम पंचायत के सरपंच श्री मियाँ हुसैन सहित पदाधिकारी तथा अधिकारी उपस्थित रहे।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मदार-पालनपुर सेक्शन में इंजीनियरिंग कार्य हेतु ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी

(जीएनएस)। उत्तर पश्चिम रेलवे के मदार-पालनपुर सेक्शन के सोमेसर और जवाली स्टेशनों के बीच ब्रिज नंबर 613 किमी 464/7-8 पर आरसीसी बॉक्स लॉन्चिंग हेतु ब्लॉक लिया गया है। जिसके कारण साबरमती-जोधपुर एक्सप्रेस निरस्त तथा कुछ ट्रेनें डायवर्ट एवं रिशेड्यूल रहेगी। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

निरस्त ट्रेन

▸▸ 05 और 6 दिसंबर 2025 को साबरमती से चलने वाली ट्रेन संख्या 14822 साबरमती-जोधुपर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

▸▸ 04 और 5 दिसंबर 2025 को जोधपुर से चलने वाली ट्रेन संख्या 14821 जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

मार्ग परिवर्तित ट्रेनें

▸▸ 4 दिसंबर 2025 की ट्रेन संख्या 20943 बांद्रा टर्मिनस – भगतकी कोठी एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग महेसाणा - पालनपुर - मारवाड़ जं. - लूनी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया महेसाणा-पाटन-भीलड़ी-समदड़ी-लूनी के रास्ते चलेगी। इस दौरान इस ट्रेन को भीलड़ी,मारवाड़ भीनवाल-जालोर-समदड़ी-लूनी स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है।

▸▸ 5 दिसंबर 2025 की ट्रेन संख्या 20944 भगतकी कोठी - बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग लूनी- मारवाड़ जं.- पालनपुर - महेसाणा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया लूनी-समदड़ी-भीलड़ी-पाटन - महेसाणा के रास्ते चलेगी। इस दौरान इस ट्रेन को भीलड़ी,मारवाड़ भीनवाल-जालोर-समदड़ी-लूनी स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है।

▸▸ 5 दिसंबर 2025 की ट्रेन संख्या 20946 हड़पसर - जोधपुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग महेसाणा -पालनपुर - मारवाड़ जं. - लूनी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया महेसाणा-पाटन-भीलड़ी-समदड़ी-लूनी के रास्ते चलेगी। इस दौरान इस ट्रेन को भीलड़ी,मारवाड़ भीनवाल-जालोर-समदड़ी-लूनी स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है।

रिशेड्यूल ट्रेनें

▸▸ 05 दिसंबर 2025 की ट्रेन संख्या 19223 साबरमती-जम्मूतवी एक्सप्रेस साबरमती से 3.15 घंटे विलंब से प्रस्थान करेगी।

▸▸ 05 दिसंबर 2025 की ट्रेन संख्या 19031 साबरमती-योगनगरी ऋषिकेश योगा एक्सप्रेस साबरमती से 2.15 घंटे विलंब से प्रस्थान करेगी।

▸▸ 04 दिसंबर 2025 की ट्रेन संख्या 14701 श्रीगंगानगर-बांद्रा टर्मिनस अरावली एक्सप्रेस श्री गंगानगर से 6.00 घंटे विलंब से प्रस्थान करेगी।

▸▸ 05 दिसंबर 2025 की ट्रेन संख्या 14707 हनुमानगढ़-दादर रणकपुर एक्सप्रेस हनुमानगढ़ से 3.00 घंटे विलंब से प्रस्थान करेगी।

ट्रेनों के ठहराव, संरचना, मार्ग और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

विरार स्टेशन पर प्लेटफॉर्म विस्तार कार्य के चलते लोकल सेवा में अस्थायी परिवर्तन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा विरार – दहानू रोड खंड के बीच तीसरी और चौथी लाइन परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म कार्य किया जा रहा है। इन कार्यों के तहत विरार स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 3ए का विस्तार और नए होम प्लेटफॉर्म 5ए का निर्माण किया जा रहा है।
पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ये कार्य स्टेशन की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ भविष्य में बढ़ते रेल यातायात के सुचारू संचालन में सहायक होंगे। इन कार्यों के कारण पश्चिम रेलवे की निम्नलिखित लोकल सेवा में तत्काल प्रभाव से अगली सूचना तक बदलाव किया जा रहा हैः
1.दादर से 10:55 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 92083 दादर – विरार लोकल अब वसई रोड स्टेशन पर शॉर्ट-टर्मिनेट होगी।
2.विरार से 12:10 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 92100 विरार – दादर लोकल अब वसई रोड से 12:20 बजे प्रारंभ होगी।
इसके अतिरिक्त, अगली सूचना तक विरार स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3ए पर कोई भी ट्रेन सेवा संचालित नहीं की जाएगी। यात्रियों से अनुरोध है कि वे इस परिचालन परिवर्तन पर ध्यान दें।

तत्काल बुकिंग प्रणाली में बदलाव: अहमदाबाद मण्डल से चलने वाली और चार प्रतिष्ठित ट्रेनों के लिए OTP प्रमाणीकरण 5 दिसंबर से लागू

(जीएनएस)।पश्चिम रेलवे द्वारा रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार तत्काल बुकिंग प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू किया जा रहा है। अब तत्काल टिकट केवल सिस्टम द्वारा भेजे गए वन टाइम पासवर्ड (OTP) के सत्यापन के बाद ही जारी किए जाएंगे। यह ओटीपी उस मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, जो यात्री द्वारा बुकिंग के समय दिया जाएगा। ओटीपी का सफल सत्यापन होने पर ही टिकट जारी किया जाएगा।
यह OTP-आधारित तत्काल प्रमाणीकरण प्रणाली 05 दिसम्बर, 2025 से निम्नलिखित ट्रेनों पर लागू हो जाएगी
1. ट्रेन संख्या 12957 साबरमती-नई दिल्ली स्वर्णजयंती राजधानी एक्सप्रेस
2. ट्रेन संख्या 12297 अहमदाबाद-पुणे दुरन्तो एक्सप्रेस
3. ट्रेन संख्या 12462 साबरमती-जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस
4. ट्रेन संख्या 12268/12267 हापा–मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस
5. ट्रेन संख्या 12009/12010 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद शताब्दी (01.12.2025 से लागू)
नई प्रणाली कंप्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों, अधिकृत एजेंटों, आईआरसीटीसी वेबसाइट तथा आईआरसीटीसी मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाने वाली सभी तत्काल बुकिंग पर लागू होगी। इस बदलाव का उद्देश्य तत्काल बुकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना तथा वास्तविक यात्रियों को तत्काल टिकट प्राप्त करने में बेहतर सुविधा प्रदान करना है।
यात्रियों से अनुरोध है कि वे बुकिंग के समय वैध मोबाइल नंबर अवश्य उपलब्ध कराएँ, ताकि OTP सत्यापन प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। पश्चिम रेलवे द्वारा सभी यात्रियों से इस महत्वपूर्ण बदलाव पर ध्यान देने का आग्रह किया गया है।

5 और 6 दिसंबर को साबरमती-खोडियार के बीच स्थित रेलवे क्रॉसिंग नं. 240 (त्रागढ रोड फाटक) बंद रहेगा

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे अहमदाबाद मंडल के साबरमती-खोडियार स्टेशनों के बीच स्थित रेलवे क्रॉसिंग नं. 240 किमी 773/4-6 (त्रागढ़ रोड फाटक) 05 दिसंबर, 2025 को प्रातः 08.00 बजे से 06 दिसंबर, 2025 को सायः 20.00 बजे तक ओवरहॉलिंग एवं मरम्मत कार्य हेतु बंद रहेगा
सड़क उपयोगकर्ता इस अवधि के दौरान रेलवे क्रॉसिंग नंबर 241 अंडरपास वाया गोदरेज गार्डन सिटी और एस. जी. हाईवे से आवागमन कर सकते हैं।

एमसीएक्स पर सोना वायदा 642 रुपये और चांदी वायदा 2704 रुपये लुढ़काः क्रूड ऑयल वायदा में 18 रुपये फिसला

कमोडिटी वायदाओं में 34076.3 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 84233.1 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवरः सोना-चांदी के वायदाओं में 25885.15 करोड़ रुपये का हुआ कारोबारः बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 31070 पॉइंट के स्तर पर

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 118315. करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 34076.3 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 84233.1 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का दिसंबर वायदा 31070 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 1730.96 करोड़ रुपये का हुआ।
कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 25885.15 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा 130799 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 130799 रुपये और नीचे में 129454 रुपये पर पहुंचकर, 130462 रुपये के पिछले बंद के सामने 642 रुपये या 0.49 फीसदी औंधकर 129820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-गिनी दिसंबर वायदा 325 रुपये या 0.31 फीसदी घटकर 104080 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-पेटल दिसंबर वायदा 39 रुपये या 0.3 फीसदी घटकर 13043 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। सोना-मिनी दिसंबर वायदा 127974 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 128328 रुपये और नीचे में 126900 रुपये पर पहुंचकर, 507 रुपये या 0.4 फीसदी घटकर 127467 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-टेन दिसंबर वायदा प्रति 10 ग्राम 129283 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 129648 रुपये और नीचे में 128642 रुपये पर पहुंचकर, 129575 रुपये के पिछले बंद के सामने 594 रुपये या 0.46 फीसदी घटकर 128981 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था।
चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 182621 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 182887 रुपये और नीचे में 177289 रुपये पर पहुंचकर, 182352 रुपये के पिछले बंद के सामने 2704 रुपये या 1.48 फीसदी औंधकर 179648 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 2625 रुपये या 1.43 फीसदी घटकर 180363 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 2717 रुपये या 1.48 फीसदी की गिरावट के साथ 180308 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।
मेटल वर्ग में 3976.11 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा दिसंबर वायदा 4.45 रुपये या 0.41 फीसदी घटकर 1072.1 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता दिसंबर वायदा 2 रुपये या 0.65 फीसदी लुढ़ककर 307 रुपये प्रति किलो बोला गया। इसके सामने एल्यूमीनियम दिसंबर वायदा 1.5 रुपये या 0.54 फीसदी औंधकर 276.75 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा दिसंबर वायदा 45 पैसे या 0.25 फीसदी की नरमी के साथ 182.45 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।
इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 4227.33 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल दिसंबर वायदा 5370 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5372 रुपये और नीचे में 5331 रुपये पर पहुंचकर, 18 रुपये या 0.34 फीसदी घटकर 5338 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी दिसंबर वायदा 18 रुपये या 0.34 फीसदी लुढ़ककर 5338 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 450.8 रुपये के भाव पर खूलकर, 455.6 रुपये के दिन के उच्च और 447.4 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 450 रुपये के पिछले बंद के सामने 1.4 रुपये या 0.31 फीसदी लुढ़ककर 448.6 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी दिसंबर वायदा 1 रुपये या 0.22 फीसदी की गिरावट के साथ 449 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था। कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 892.3 रुपये के भाव पर खूलकर, 80 पैसे या 0.09 फीसदी के सुधार के साथ 904 रुपये प्रति किलो बोला गया।
कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 11355.88 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 14529.27 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 3241.46 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 297.07 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 18.44 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 418.60 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।
इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 370.55 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 3841.84 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 1.33 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 0.19 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।
ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 14430 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 64312 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 20319 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 331231 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 31577 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 18630 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 42931 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 121193 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 16170 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 35980 लोट के स्तर पर था। इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 31337 पॉइंट पर खूलकर, 31337 के उच्च और 30932 के नीचले स्तर को छूकर, 274 पॉइंट घटकर 31070 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।
कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल दिसंबर 5400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 14.9 रुपये की गिरावट के साथ 91.4 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 450 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.05 रुपये की गिरावट के साथ 24.7 रुपये हुआ। सोना दिसंबर 136000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 154 रुपये की गिरावट के साथ 861 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 185000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1506.5 रुपये की गिरावट के साथ 5018.5 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1080 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.35 रुपये की गिरावट के साथ 21.84 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 315 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.02 रुपये की गिरावट के साथ 2.64 रुपये हुआ। पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल दिसंबर 5300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 1.4 रुपये की गिरावट के साथ 103.2 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 450 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 20 पैसे के सुधार के साथ 25.95 रुपये हुआ।
सोना दिसंबर 120000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 22 रुपये की बढ़त के साथ 254 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 165000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 243 रुपये की बढ़त के साथ 1663.5 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 295 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 20 पैसे के सुधार के साथ 0.9 रुपये हुआ।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर में 9000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनों को नियुक्ति पत्र वितरित करने का गौरवशाली समारोह आयोजित

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- ▸▸ आंगनबाड़ी बच्चे के जीवन निर्माण की पहली सीढ़ी है
- ▸▸ राज्य में 53,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत, 170 और आंगनबाड़ी केंद्रों का ई-लोकार्पण और शिलान्यास संपन्न
- ▸▸ राज्य सरकार प्रधानमंत्री के नारी शक्ति से राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को साकार करने के लिए माता के पोषण एवं स्वास्थ्य के साथ ही बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य एवं प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है

▸▸ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को 'विकसित भारत@2047' के लिए स्वस्थ पीढ़ी तैयार करने की अहम जिम्मेदारी निभानी है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केवल सरकारी सेवा में नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य को और भी सशक्त बनाने के मिशन में जुड़ीं हैं : डॉ. मनीषाबेन वकील, महिला एवं बाल विकास मंत्री

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में महिला एवं बाल विकास मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. मनीषाबेन वकील की प्रेरक उपस्थिति में राज्य की आंगनबाड़ियों में नवनियुक्त 9000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। राज्यभर में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण के जोनवार कार्यक्रमों में मंत्रियों और पदाधिकारियों ने नियुक्ति पत्र वितरित किए और सभी ने गांधीनगर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का प्रसारण देखा।
मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनों को बधाई देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी बच्चे के जीवन निर्माण की पहली सीढ़ी है। आंगनबाड़ी बहनों को देश के भविष्य इन नन्हें बच्चों के समृद्ध विकास की अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी है।
उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों का आह्वान किया कि वे उन्हें मिले 'सुपोषित और विकसित गुजरात से' 'विकसित भारत-समृद्ध भारत' बनाने के सेवा अवसर को सार्थक करने हेतु 'विकसित भारत@2047' के लिए स्वस्थ पीढ़ी तैयार करें।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नारी शक्ति से राष्ट्र निर्माण का जो लक्ष्य दिया है, उसे साकार करने के लिए राज्य सरकार माताओं के पोषण और स्वास्थ्य के साथ ही नन्हें बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल मानस का संस्कार सिंचन करके उन्हें भविष्य का नागरिक बनाने का दायित्व निभाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनें माता यशोदा की तरह बच्चों का लालन-पालन और जीवन निर्माण करती हैं।
उन्होंने इस संदर्भ में इस बात का भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री ने ऐसी बहनों को माता यशोदा का गौरव सम्मान दिया है और आंगनबाड़ी केंद्र को नंद घर की पहचान दी है। श्री पटेल ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी ने एक समय पुराने मकानों, पंचायत घरों और मंदिरों में चलने वाले बाल मंदिरों की स्थिति को बदलने का विजन दिया और गुजरात में संपूर्ण सुविधा युक्त आंगनबाड़ी-नंद घरों का निर्माण कराया। इसके परिणामस्वरूप राज्य में 53,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं।
मुख्यमंत्री ने इस समारोह में 170 और नए आंगनबाड़ी केंद्रों का ई-लोकार्पण एवं शिलान्यास करते हुए आने वाले वर्षों में 10 हजार से अधिक नए नंद घर बनाने की राज्य सरकार की योजना की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से महिलाओं एवं बच्चों के पोषण की निरंतर चिंता करते हुए राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों के लिए दूध संजीवनी योजना के तहत फोर्टिफाइड फ्लैवर्ड दूध के अलावा गर्भवती माताओं को प्रोटीन युक्त आहार प्रदान करने के लिए पोषण सुधा योजना, टेक होम राशन और मुख्यमंत्री मातृशक्ति जैसी कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। इतना ही नहीं, आंगनबाड़ी से लेकर प्राथमिक स्कूल तक के 41 लाख से अधिक बच्चों के लिए 'मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना' भी शुरू की गई है। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. मनीषाबेन वकील ने राज्य की आंगनबाड़ियों में नियुक्ति पाने वाली सभी बहनों को बधाई दी और कहा कि आज से आप सभी सरकारी सेवा में नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य को और अधिक सशक्त बनाने के मिशन में जुड़ी हैं। आप सभी कल के नागरिक यानी इन बच्चों की पहली शिक्षिका बनने जा रही हैं। आप जो संस्कार, शिक्षा और पोषण का बीज रोपेंगे, उसी से आने वाले कल का गुजरात खिलेगा।

पश्चिम रेलवे- अहमदाबाद

विभिन्न प्रमुख पुलों का निर्माण

ई-निविदा संख्या: DyCE-C-V-NLY-JAKHAU-03 दिनांक: 03.12.2025

भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए और उनकी की ओर से उप मुख्य अभियंता (निर्माण) (V), अहमदाबाद, निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदा आमंत्रित करते हैं:

(1) ई-निविदा संख्या: DyCE-C-V-NLY-JAKHAU-03

(2) कार्य का नाम:पश्चिम रेलवे पर अहमदाबाद मंडल के नलिया-जखाऊ पोर्ट सेक्शन के बीच नई बीजी लाइन के संबंध में नलिया से जखाऊ के बीच कार्य के सफल समापन के लिए आवश्यक पिचिंग, टो वॉल, फ्लोर प्रोटेक्शन और अन्य विविध कार्यों सहित विभिन्न प्रमुख पुलों का निर्माण।

(3) अनुमानित लागत: ₹ 164,24,01,793.42

(4) बिड सिक्योरिटी: ₹ 83,62,000.00

(5) निविदा का प्रकार: टू पैकेट सिस्टम

(6) पूर्णता अवधि: 15 माह (पंद्रह माह), मानसून सहित

(7) निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय: 24.12.2025 को 15:00 बजे

(8) ई-निविदा खोलने की तिथि व समय: 24.12.2025 को 15:00 बजे के बाद कभी भी

(9) निविदा की संपूर्ण जानकारी देखने हेतु वेबसाइट/नोटिस बोर्ड का स्थान तथा कार्यालय का पता: निविदा की संपूर्ण जानकारी एवं पात्रता मापदंड पश्चिम रेलवे की वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। **कार्यालय:** उप मुख्य अभियंता (निर्माण) V, निर्माण भवन, प्रथम तल, जीसीएस हॉस्पिटल के सामने, नारोडा रोड, DRM कार्यालय के पास, अहमदाबाद–382345 **किसी भी स्पष्टीकरण हेतु फर्म कार्यालय समय में व्यक्तिगत रूप से या मोबाइल नंबर 9724093252 पर संपर्क कर सकती है।** CPM 088

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: twitter.com/WesternRly

बंगाल की उपेक्षा का आरोप गलत, राज्य के विकास में टीएमसी के अवरोध का खुलासा: राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब

(जीएनएस)। नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन राज्यसभा में गुरुवार को केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक 2025 पर बहस के दौरान पश्चिम बंगाल के विकास को लेकर चर्चा गरमाई। टीएमसी के सदस्यों ने केंद्र सरकार पर राज्य की अनदेखी और विकास फंड न मिलने का आरोप लगाया, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि राज्य का विकास टीएमसी की नीतियों और भ्रष्टाचार के कारण ठप हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र ने कभी भी बंगाल को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि राज्य की अपनी सरकार ने विकास की प्रक्रिया में बाधा डाली।

टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल को 1.75 लाख करोड़ रुपये के जीएसटी मुआवजा और अन्य फंड्स का भुगतान नहीं किया गया। इस पर वित्त मंत्री ने बताया कि 1 अप्रैल 2011 से 30 सितंबर 2025 तक बंगाल से 448 लिस्टेड कंपनियां और 6,447 अनलिस्टेड कंपनियां राज्य छोड़ गईं, जिससे राज्य की जीडीपी ग्रोथ दर पहले 10 प्रतिशत से घटकर अब मात्र 3 प्रतिशत रह गई है। उन्होंने यह भी कहा कि आयुष्मान भारत योजना से राज्य ने 2019 में खुद बाहर निकलने का निर्णय लिया, जो जनता के हित में नहीं था। केंद्र की योजनाओं में हुए अनियमितताओं और टीएमसी के भ्रष्टाचार ने राज्य में निवेश और विकास को रोक दिया। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल में विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए हैं, लेकिन राज्य की भ्रष्टाचारपूर्ण नीतियों और उद्योगों के पलायन ने विकास को बाधित किया।

मनरेगा बकाया राशि के आरोपों पर भी वित्त मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि मार्च 2022 से नियमों का पालन न करने के कारण धनराशि रोक दी गई थी। जुलाई 2025 में राज्य ने चार जिलों से 4.81 करोड़ रुपये वसूले जाने और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की जानकारी स्वीकार की। वित्त मंत्री के जवाब के दौरान टीएमसी सांसदों ने असंतुष्ट होकर वॉकआउट कर दिया, जिससे सदन में हलचल रही।

इस बहस के बीच लोकसभा में भी विवाद हुआ जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 'हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल' के लाभ हिंदी में समझा रही थीं। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि वे बंगाली हैं और हिंदी ठीक से समझ नहीं पा रहे। स्पीकर जगदंबिका पाल ने कहा कि सदन में सभी भाषाओं का लाइव अनुवाद उपलब्ध है और विधेयक की कॉपी पहले ही प्राप्त हो चुकी है। इस पर निर्मला सीतारमण ने तंज के साथ कहा कि चाहे मैं हिंदी बोलूं, तमिल बोलूं या अंग्रेजी बोलूं, ट्रांसलेटर मौजूद हैं और आप अपनी भाषा में सुन सकते हैं।

विश्लेषकों का कहना है कि इस बहस ने स्पष्ट कर दिया कि केंद्र ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए लगातार प्रयास किए हैं, लेकिन राज्य सरकार की नीतियां, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अव्यवस्था विकास को रोकने का प्रमुख कारण बन रही हैं। वित्त मंत्री ने राज्य के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं, उद्योगों के पलायन, विकास परियोजनाओं और नागरिक कल्याण से जुड़े सभी मुद्दों पर केंद्र की ओर से तथ्य प्रस्तुत किए। इस बहस ने संसद में न केवल वित्तीय दृष्टिकोण से, बल्कि प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मोड़ प्रस्तुत किया।

इस पूरी घटना से यह संदेश भी स्पष्ट हुआ कि राज्य और केंद्र के बीच विकास को लेकर केवल आरोप-प्रत्यारोप का खेल नहीं चल रहा, बल्कि वास्तविक स्थिति पर आंकड़ों और नीतियों के आधार पर बहस हो रही है। वित्त मंत्री के ठोस जवाब और टीएमसी की प्रतिक्रिया ने यह दिखा दिया कि पश्चिम बंगाल के विकास में बाधाएं केवल राजनीतिक हैं और केंद्र लगातार राज्य को वित्तीय और प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराता रहा है।

IAS दुल्हन और IPS दूल्हे की भव्य और सादगीपूर्ण शादी, चंबल रिवर फ्रंट बना नजारे का आकर्षण

(जीएनएस)। कोटा। राजस्थान के कोटा जिले में हाल ही में हुई एक अनोखी शादी ने प्रशासनिक हलकों से लेकर सोशल मीडिया तक खूब सुर्खियां बटोरी हैं। यह शादी किसी फिल्मी सेट से कम नहीं लग रही थी, क्योंकि इसमें सादगी और भव्यता का अद्भुत मिश्रण देखने को मिला। राजस्थान कैडर की आईएएस अधिकारी चारु और कोटा ग्रामीण के आईपीएस एसपी सुजीत शंकर ने देश के पहले हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट पर सात फेरे लिए।

चंबल रिवर फ्रंट, जिसकी कुल लागत 1200 से 1400 करोड़ रुपये है और यह छह किलोमीटर लंबा है, ने शादी समारोह की भव्यता को और बढ़ा दिया। रिवर फ्रंट की प्रमुख विशेषताओं में चंबल माता की 225 फीट ऊंची संगमरमर की मूर्ति, ब्रह्मा घाट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी और राजस्थान के नौ क्षेत्रों की विशिष्ट वास्तुकला को दर्शाने वाले 26-27 घाट शामिल हैं। इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल पर आयोजित शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और लोगों ने इसे बेहद अनोखा और यादगार बताया है।

आईपीएस सुजीत शंकर बिहार के रहने वाले हैं और वर्तमान में कोटा ग्रामीण जिले के एसपी के रूप में तैनात हैं। वहीं, आईएएस चारु उत्तर प्रदेश की निवासी हैं और हाल ही में शादी के आधार पर त्रिपुरा कैडर से राजस्थान कैडर में आई हैं। उनकी पहली पोस्टिंग रामगंज मंडी में एसडीएम के रूप में हुई थी, जो कोटा ग्रामीण क्षेत्र में आता है। दोनों की प्रशासनिक पृष्ठभूमि और कैडर परिवर्तन ने इस विवाह को प्रशासनिक हलकों में पहले से ही चर्चा का विषय बना दिया था।

शादी से पूर्व और दौरान होने वाले कार्यक्रमों में कई उच्च स्तर के नेता और अधिकारी शामिल हुए। 29 नवंबर को हुए संगीत समारोह में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मौजूद रहे, जबकि 30 नवंबर को विवाह समारोह में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। इसके अलावा, पुलिस और प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी समारोह में शामिल हुए। इसके बावजूद समारोह में किसी प्रकार का दिखावा नहीं किया गया और पूरी शादी सादगी और आत्मीयता के साथ संपन्न हुई। दोनों परिवारों ने अतिथियों का स्वागत पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार किया, जिससे समारोह का माहौल और भी खास बन गया।

इस शादी ने दिखा दिया कि भव्यता और सादगी का सुंदर मेल कैसे बनाया जा सकता है। प्रशासनिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक उत्सव का यह अनूठा संगम न केवल कोटा बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें और वीडियो लोग बड़े चाव से साझा कर रहे हैं और इसे एक यादगार और प्रेरणादायक आयोजन बता रहे हैं।

इस तरह आईएएस चारु और आईपीएस सुजीत शंकर की शादी ने प्रशासनिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत दृष्टि से एक मिसाल कायम की है, जो आने वाले समय तक लोगों की यादों में ताजा बनी रहेगी।

बंगाल में वक्फ संशोधन कानून लागू, ममता बनर्जी ने सुरक्षा और धार्मिक सौहार्द बनाए रखने का जताया आश्वासन

(जीएनएस)। कोलकाता। पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून को लागू करने के सात महीने बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे लागू करने का औपचारिक ऐलान किया। इस कदम को लेकर कई सवाल उठ रहे थे कि आखिर मोदी सरकार द्वारा लागू कानून को ममता बनर्जी की सरकार ने क्यों लागू किया। गुरुवार को मुर्शिदाबाद में आयोजित एक जनसभा में ममता बनर्जी ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि यह कानून मुस्लिम और अन्य धार्मिक संस्थाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका उद्देश्य राज्य में धार्मिक सौहार्द बनाए रखना है और किसी की संपत्ति या अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे।

ममता बनर्जी ने कहा, "जैसे मैं जगन्नाथ धाम में विश्वास करती हूं, वैसे ही मुस्लिम कब्रिस्तानों का भी सम्मान करती हूं। पुजारियों के साथ-साथ मैं मुअज्जमों और लोक कलाकारों को भत्ता देती हूं। इसलिए हमने यह कानून लागू किया है और इसे लागू करते रहेंगे। कुछ लोग वक्फ एक्ट को गलत समझा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने किसी की संपत्ति या अधिकार छीनने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। यह पूरी तरह से झूठ है।" मुख्यमंत्री ने विस्तार से बताया कि पहले वक्फ बोर्ड के पास वक्फ संपत्तियों का अपलोड प्रोसेस था और कुल 2,82 हजार प्रॉपर्टी सेंट्रल पोर्टल पर दर्ज थीं। अब राज्य सरकार ने WMC पोर्टल बनाया है, जिससे अपलोड और मॉनिटरिंग का कार्य पारदर्शी तरीके से हो रहा है। ममता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया गया है और राज्य सरकार किसी की प्रॉपर्टी जबरन नहीं छीनेगी। उन्होंने स्पष्ट किया, "किसी की बात मत सुनो, मैं जो कह रही हूं, यहीं खड़े होकर कह रही हूं। आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है।"

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने SIR फॉर्म को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और तब तक नहीं भरेंगी जब तक पूरे राज्य के लोग पूरा फॉर्म जमा नहीं कर देते। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि सरकार आम लोगों के साथ है, किसी का नाम नहीं छूटेगा और अगर किसी को बांग्लादेश भेजा भी गया है, तो सरकार उन्हें वापस लाएगी। ममता बनर्जी ने सोनाली खातून के मामले का भी उल्लेख किया। प्रेग्नेंट सोनाली खातून को बांग्लादेश भेज दिया गया था, लेकिन राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वापस लाने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं सोनाली खातून के लिए सुप्रीम कोर्ट गई हूं। वह प्रेग्नेंट मां हैं। मैंने केस फाइल किया और कहा कि उसे वापस लाया जाए।"

इस तरह ममता बनर्जी ने वक्फ संशोधन कानून को लागू करने का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट किया—राज्य में धार्मिक संस्थाओं और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा बनाए रखना, प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना और लोगों के सुरक्षा अधिकारों की रक्षा करना। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि SIR या किसी अन्य प्रक्रिया के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है, बस अपने कागजात सही तरीके से जमा करें।

तंबाकू उत्पादों पर नया कर ढांचा: केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश, जीएसटी मुआवजा उपकर 2025 में समाप्त होने के बाद लागू होगा नया नियम

(जीएनएस)। नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र में गुरुवार का दिन वित्तीय और कर नीति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित हुआ, जब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक 2025 पेश किया। इससे एक दिन पहले लोकसभा ने विधेयक को पारित कर दिया था और अब राज्यसभा में विचार-विमर्श जारी है। यह विधेयक तंबाकू उत्पादों पर लागू कर संरचना में बड़े बदलाव का मार्ग प्रशस्त करता है और जीएसटी मुआवजा उपकर की समाप्ति के बाद कर व्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने का प्रयास है। वर्तमान में लागू जीएसटी मुआवजा उपकर 2017 में जीएसटी लागू होने के समय शुरू किया गया था, ताकि राज्यों को इस नए कर ढांचे से होने वाली राजस्व हानि की भरपाई हो सके। यह उपकर तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त कर के रूप में लगाया गया था और वर्ष 2025 में समाप्त होने वाला है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक इसी व्यवस्था की जगह लेने के लिए पेश किया गया है, ताकि सिगरेट, सिगार, जर्दा, खैनी और अन्य तंबाकू उत्पादों पर कर का बोझ संतुलित रूप से कायम रहे।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम केवल वित्तीय स्थिरता के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य नीतियों के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तंबाकू उत्पादों पर कर का स्तर केवल राज्य और केंद्र के राजस्व के लिए ही नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं के व्यवहार को प्रभावित करने और तंबाकू के सेवन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भी निर्धारित किया जाता है। विधेयक में यह सुनिश्चित किया गया है कि जीएसटी मुआवजा उपकर खत्म होने के बाद भी कर का भार न तो अचानक बढ़े और न घटे, जिससे राजस्व में गिरावट न आए और स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ प्रभावित न हों।

राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सांसदों ने तंबाकू उत्पादों के स्वास्थ्य जोखिम, राज्यों की वित्तीय स्थिति और कर नीति की स्थिरता पर अपने विचार रखे। कई सांसदों ने जोर दिया कि नई कर नीति तंबाकू के सेवन पर नियंत्रण के लिए प्रभावी साधन होनी चाहिए, जबकि कुछ ने राज्यों की आय में संभावित बदलाव को लेकर चिंता जताई। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि नया उत्पाद शुल्क जीएसटी मुआवजा उपकर की समाप्ति के बाद राज्यों के राजस्व को संतुलित बनाए रखने के साथ-साथ उपभोक्ताओं के लिए कर संरचना में पारदर्शिता और स्थिरता भी सुनिश्चित करेगा।

विश्लेषकों के अनुसार, इस विधेयक के लागू होने के बाद तंबाकू उत्पादों की कीमतों में अचानक बदलाव की संभावना कम होगी और सरकार राज्यों को समय पर राजस्व उपलब्ध कराकर वित्तीय संतुलन बनाए रखने में सक्षम होगी। साथ ही, यह कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अहम है क्योंकि उच्च कर दरों और स्थिर कर संरचना के माध्यम से तंबाकू के सेवन को नियंत्रित करने की दिशा में नीति प्रभावी रहेगी।

विधेयक के पारित होने के साथ ही भारत में तंबाकू उत्पादों पर कर नीति में एक नया अध्याय शुरू होगा। यह केवल वित्तीय और राजस्वीय पहल नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहल है जो देश के स्वास्थ्य और आर्थिक दोनों दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आगामी वर्षों में इस कर ढांचे का प्रभाव राज्यों की वित्तीय स्थिति और तंबाकू उपभोग के पैटर्न दोनों पर देखने को मिलेगा।

दिल्ली-एनसीआर में हवा जहरीली, प्राणवायु पर संकट गहराया; AQI 304 दर्ज, स्वास्थ्य पर गंभीर असर

(जीएनएस)। नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या लगातार विकराल होती जा रही है। शुक्रवार सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 304 रिकॉर्ड किया गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है। यह स्तर न केवल सामान्य लोगों के लिए बल्कि बुजुर्गों, बच्चों और अस्थमा व फेफड़ों की समस्या वाले मरीजों के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के कई क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में है। बागपत में AQI 307, गाजियाबाद 302, ग्रेटर नोएडा 285, गुरुग्राम 293, हापुड़ 336 और नोएडा 308 दर्ज किया गया। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि न केवल राजधानी बल्कि उसके उपनगरों में भी हवा जहरीली और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बनी हुई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए बताया कि दिल्ली का आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, सुबह हल्का कोहरा छाया रहेगा और शीतलहर का असर कुछ इलाकों में महसूस होगा। अधिकतम तापमान 22-24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4-6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हवा दिनभर उत्तर-पश्चिम दिशा से 10-12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो प्रदूषण को फैलने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है।

छवि और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेताया है कि प्रदूषण का यह स्तर लंबे समय तक रहने पर श्वसन संबंधी बीमारियों, आंखों व गले में जलन, सिरदर्द और हृदय रोगों के खतरे को बढ़ा सकता है। 6 दिसंबर को भी आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा और सुबह हल्का कोहरा रहेगा। अधिकतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7-9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिन और रात में हवा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी, जिससे कुछ हद तक प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है।

CPCB के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के मानदंड इस प्रकार हैं: 0-50 'अच्छा', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 201-300 'खराब', 301-400 'बेहद खराब' और 401-500 'गंभीर'। दिल्ली में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में वाहनों का योगदान 20.45%, पराली जलाने का 1.97%, निर्माण और ध्वंस गतिविधियों का 3.10%, और आवासीय क्षेत्रों का 5.30% है।

विशेषज्ञों का कहना है कि ठंडी हवाओं और कोहरे के कारण प्रदूषण के कण जमीन के पास ठहर जाते हैं, जिससे सांस लेना और भी मुश्किल हो जाता है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे सुबह-शाम बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें, बच्चों और बुजुर्गों को प्रदूषण वाले इलाकों में कम से कम भेजें और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि से बचें। राजधानी और एनसीआर की हवा फिलहाल खतरनाक स्तर पर है और इसका प्रभाव हर सांस पर महसूस किया जा रहा है।

देशभर में बदल जाएगा टोल सिस्टम: एक साल में खत्म होगी पारंपरिक व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन से हाईवे यात्रा होगी आसान

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश में टोल सिस्टम के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में ऐलान किया कि वर्तमान टोल संग्रह प्रणाली अगले एक साल के भीतर पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी। इसके स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे यात्रियों को हाईवे पर रुक-रुक कर टोल देने की झंझट से मुक्ति मिलेगी और यात्रा अधिक सुगम और तेज़ होगी। मंत्री ने बताया कि नई प्रणाली पहले ही 10 प्रमुख स्थानों पर सफलतापूर्वक प्रयोगात्मक रूप में लागू की जा चुकी है। अगले एक साल के भीतर इसे पूरे देश में विस्तारित कर दिया जाएगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा, "टोल सिस्टम खत्म हो जाएगा। टोल के नाम पर कोई रोक नहीं होगी। देशभर में एक साल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन लागू हो जाएगा।"

यह नई व्यवस्था टोल नाकों पर वाहनों को रुकने की बाध्यता समाप्त कर देगी। वर्तमान में देशभर में 4,500 से अधिक हाईवे परियोजनाओं का काम चल रहा है, जिनकी कुल लागत लगभग 10 लाख करोड़ रुपये है। गडकरी ने बताया कि नए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में वाहन की केवल एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, नंबर प्लेट की फोटो ली जाएगी और फास्टैग के माध्यम से शुल्क सीधे वाहन के बैंक खाते से कट जाएगा। इस प्रक्रिया से पारदर्शिता बढ़ेगी, टोल प्लाज़ा पर लगने वाली लंबी कतारें समाप्त होंगी और हाईवे यात्रा का समय भी बच जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल यातायात को सुगम बनाएगा, बल्कि टोल प्रबंधन में भ्रष्टाचार और मानव त्रुटियों को भी कम करेगा। फास्टैग आधारित सिस्टम से प्रत्येक वाहन का रिकॉर्ड डिजिटल तरीके से रखा जाएगा, जिससे टोल संग्रह की निगरानी और संचालन अधिक प्रभावी और पारदर्शी हो सकेगा।

मंत्री गडकरी ने आगे कहा कि इस प्रणाली से देश में व्याप्त पुराने टोल प्रबंधन की जटिलताओं को दूर किया जाएगा। इससे यात्रियों का समय बचेगा और लॉजिस्टिक संचालन में सुधार होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बदलाव के साथ ही हाईवे यात्रा में आराम और सुरक्षा दोनों बढ़ेगी।

देशभर में इस इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम के कार्यान्वयन के बाद यह अपेक्षित है कि लंबी कतारों और टोल नाकों पर रुकने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और ट्रैफिक जाम की समस्या भी काफी हद तक कम हो जाएगी। यह पहल डिजिटल इंडिया की दिशा में भी एक बड़ा कदम मानी जा रही है, जो देश में हाईवे यात्रा के अनुभव को पूरी तरह बदल देगी और यात्रियों के लिए तेज़, सुरक्षित और सुविधाजनक मार्ग सुनिश्चित करेगी।

आगामी VGRC, राजकोट में विश्व मंच पर चमकेगी टंगालिया हस्तकला की पहचान, टंगालिया कारीगरों की कला और उपलब्धियाँ होंगी प्रमुख आकर्षण

टंगालिया हस्तकला के माध्यम से पद्मश्री लवजीभाई परमार गुजरात की सांस्कृतिक धरोहर को दे रहे नई शक्ति

(जीएनएस)। गांधीनगर : माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मंत्र "हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी" से प्रेरित होकर राजकोट के मारवाड़ी विश्वविद्यालय में होने वाला वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के औद्योगिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवसरों को व्यापक मंच पर प्रदर्शित करेगा। टंगालिया कला, गुजरात की लगभग 700 वर्ष पुरानी हस्तकरघा परंपरा है, जो अपने दानेदार पैटर्न के लिए जानी जाती है। सुरेंद्रनगर के डांगासिया समुदाय के कारीगर इस कला को आज भी बेहद निपुणता से संरक्षित किए हुए हैं। इसमें अतिरिक्त वेफ्ट धागों को वार्प धागों पर बारीकी से लपेटकर सुंदर ज्यामितीय डिज़ाइन बनाए जाते हैं। इसकी अनोखी तकनीक और सांस्कृतिक महत्व के कारण टंगालिया को भौगोलिक संकेत (GI) का भी दर्जा मिला है, जो इसकी विशिष्टता और परंपरा की रक्षा करता है।

कभी विलुप्त के कगार पर पहुँच चुकी यह प्राचीन कला आज फिर नई पहचान बना रही है। आज बदलते समय में दुनिया में पुरातन, हस्त निर्मित और सांस्कृतिक रूप से जुड़ी वस्तुओं की बढ़ती मांग ने इसे दोबारा जीवंत कर दिया। आज हस्त निर्मित उत्पादों की वैश्विक लोकप्रियता के चलते गुजरात के टंगालिया कारीगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहे हैं। इस पुनर्जीवन के प्रमुख सूत्रधार हैं लवजीभाई परमार, जो पारंपरिक टंगालिया बुनाई के माहिर कलाकार हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2025 में उनके योगदान को मान देते हुए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है।

लवजीभाई परमार पिछले चार दशकों से इस प्राचीन कला के संरक्षण और संवर्धन में जुटे हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया है जहाँ युवा कारीगरों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और बाज़ार से जुड़ने में मदद मिलती है। देशभर में प्रदर्शनियाँ आयोजित कर और विभिन्न विक्रेताओं से जुड़कर उन्होंने इस कला में नई ऊर्जा भर दी। इसी कारण उन्हें "टंगालियानो त्राणहार" यानी टंगालिया कला के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है।

टंगालिया कला की वैश्विक लोकप्रियता का एक उदाहरण सुरेंद्रनगर के कारीगर बलदेव मोहनभाई राठौड़ हैं। उन्होंने हॉलीवुड फिल्म "F1" के लिए अभिनेता ब्रैड पिट द्वारा पहनी गई टंगालिया शर्ट तैयार की थी। यह उपलब्धि गुजरात की इस प्राचीन कला को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाला महत्वपूर्ण क्षण बनी। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शक मंत्र "विकास भी, विरासत भी" को साकार करने में टंगालिया बुनाई की यह परंपरा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह गुजरात की सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक गौरव का मजबूत प्रतीक है।

आगामी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस इस सहयोग को और आगे बढ़ाएगी। इसमें संयुक्त उद्यमों, कौशल विकास और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के नए अवसर मिलेंगे। कच्छ और सौराष्ट्र को विशेष महत्व देने से स्पष्ट होता है कि सरकार के लिए औद्योगिक विकास के साथ-साथ सामुदायिक सशक्तीकरण, कौशल उन्नयन और पारंपरिक आजीविकाओं का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

आगामी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेन्स वैश्विक निवेशकों, स्थानीय उद्यमियों, कारीगरों और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों को एक ही मंच पर लाएगी। यह आयोजन गुजरात की आर्थिक शक्ति और उसकी सांस्कृतिक जड़ों, दोनों का उत्सव बनेगा। इसका संदेश साफ होगा कि विकास तभी सार्थक है जब वह समुदायों को आगे बढ़ाए, विरासत को सुरक्षित रखे और लोगों में गर्व की भावना पैदा करे।

गुजरात ATS की बड़ी कार्रवाई: गोवा और दमन में चला गोपनीय ऑपरेशन, पाकिस्तान समर्थित जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश; रिटायर्ड सूबेदार और महिला एजेंट गिरफ्तार

(जीएनएस)। गुजरात एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने मंगलवार देर रात दो राज्यों में फैले एक गुप्त जासूसी नेटवर्क को पकड़कर देश की सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी राहत दी है। लंबे समय से नजर में चल रहे संदिग्ध संपर्कों और डिजिटल इंटेलिजेंस ट्रैकिंग के आधार पर ATS की टीमों ने दमन और गोवा में एक साथ छापेमारी की। इस ऑपरेशन में दो आरोपियों को पकड़ा गया—दमन की रहने वाली रश्मिन रवींद्र पाल और गोवा में रह रहा भारतीय सेना का पूर्व सूबेदार एके सिंह। दोनों को देशद्रोही गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है और प्रारंभिक जांच में यह साफ हो गया है कि वे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से जुड़े नेटवर्क के जरिए संवेदनशील सैन्य जानकारी साझा कर रहे थे।

पकड़ी गई महिला रश्मिन रवींद्र पाल की संदिग्ध गतिविधियों को पिछले कुछ महीनों से खंगाला जा रहा था। ATS को सोशल मीडिया आधारित संपर्कों, कुछ संदिग्ध लेन-देन और एन्क्रिप्टेड चैट्स के जरिए मिले संकेतों ने रश्मिन की भूमिका को पहले ही उजागर कर दिया था। जैसे ही टीमों को पुख्ता तकनीकी प्रमाण मिले, दमन में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरण ATS की फॉरेंसिक टीम ने कब्जे में ले लिए हैं। शुरुआती डिजिटल एनालिसिस में यह सामने आया है कि वह पाकिस्तान स्थित ऑपरेटिव्स के साथ परिचित थी और लगातार जानकारी भेजने के बदले आर्थिक मदद प्राप्त कर रही थी।

दूसरी ओर, गोवा से पकड़ा गया पूर्व सूबेदार एके सिंह मामले में अधिक गंभीर माना जा रहा है। सेना से रिटायर होने के बाद वह गोवा में रह रहा था और ATS की स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट पिछले काफी समय से उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। जांच में यह पाया गया कि एके सिंह को सेना में अपने कार्यकाल के दौरान जिन संवेदनशील यूनिटों और इलाकों में तैनाती मिली थी, उससे जुड़ी कई जानकारियां वह दुश्मन देश को भेज चुका था। इस बात की भी आशंका है कि उसने सेना के बेस, हथियारों की मूवमेंट, और संचार व्यवस्थाओं से जुड़े कुछ अहम विवरण पाकिस्तान के खुफिया तंत्र तक पहुँचाए। इन सूचनाओं की वास्तविक सीमा और नुकसान का आकलन अब सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं।

ATS अधिकारियों ने बताया कि यह नेटवर्क किसी एक-दो व्यक्तियों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार देश के अन्य हिस्सों से भी जुड़े हो सकते हैं। कई संदिग्ध फोन नंबर, विदेशी आईडी, इंटरनेट कॉलिंग ऐप और पैसे के लेन-देन के रिकॉर्ड ATS के हाथ लगे हैं, जिनकी मदद से जांच का दायरा और बढ़ाया जा रहा है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि यह नेटवर्क पूरी गोपनीयता के साथ काम कर रहा था, जिसके पीछे एक संगठित हैंडलिंग टीम होने की आशंका है।

जांच में इस बात के भी संकेत मिले हैं कि दोनों आरोपियों को अलग-अलग समय पर पाकिस्तान से निर्देश मिलते थे। यह निर्देश कभी कोडवर्ड के रूप में आते थे तो कभी सामान्य चैट की तरह, लेकिन उनके अर्थ बेहद संवेदनशील होते थे। एके सिंह पर यह भी आरोप है कि वह पैसों की जरूरत के कारण इस नेटवर्क के संपर्क में आया और धीरे-धीरे उससे गहरी संलिप्तता बना ली।

दोनों आरोपियों से की जा रही पूछताछ के आधार पर सुरक्षा एजेंसियां अब इस नेटवर्क के अन्य संभावित सदस्यों, फंडिंग चैनल, डिजिटल कमांड सिस्टम और इनकी संचार शैली का पता लगाने में जुटी हैं। जांच अधिकारी मानते हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े और भी चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं।

गिरफ्तारियों ने देश की सुरक्षा व्यवस्था में एक बार फिर इस सच्चाई को सामने ला दिया है कि दुश्मन देश लगातार भारत की सैन्य और सामरिक जानकारी हासिल करने की कोशिश में रहता है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को तकनीकी इंटेलिजेंस, साइबर मॉनिटरिंग और मानव स्रोतों पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत महसूस होती है।

ATS की इस कार्रवाई ने न केवल एक बड़े जासूसी मॉड्यूल को ध्वस्त किया है बल्कि भविष्य में संभावित सुरक्षा खतरों को भी समय रहते रोक दिया है। इस पूरे ऑपरेशन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए देशहित सर्वोपरि है और दुश्मन देश की ओर से की जाने वाली हर साजिश का जवाब कठोर और सटीक कार्रवाई से दिया जाएगा।